3.00 P.M.

The House reassembled at three minutes past three of the clock, The Vice-Chairman (Dr. Nagen Saikia) in the Chair.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Increasing Atrocities on Scheduled Castes and other Weaker Section of Society

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, I beg to call the attention of the Minister of Welfare to increasing atrocities on the Scheduled Castes and other weaker sections of society and the action taken by Government in regard thereto.

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): उपसभाध्यक्ष जी, श्री गुरुदास दास गुप्त जी ने सरकार का ध्यान खींचा है। श्रीमन्, सरकार अनुसूचित जातियों के विरुद्ध किए गए सामाजिक भेदभाव पर बहुत चिंतित है। अस्पृश्यता से पैदा हुई किसी भी अक्षमता पर दण्ड की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया गया जिसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक तथा सामाजिक अक्षमता लागू करने के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है।

चूंकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार जारी रहें, अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य है कि इन अपराधों की जांच तथा ऐसे अपराधियों के शिकार व्यक्तियों को राहत तथा पुनर्वास और इससे संबंधित मामलों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना कर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकना। अत्याचारों के विभिन्न प्रकार के अपराधों को भी परिभाषित किया गया है और दण्ड का निर्धारण किया गया है जिसमें कारावास दण्ड, जो कि छह मास की अवधि से कम नहीं होगा और जो जुर्माने सहित पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, निर्धारित है। दूसरी बार या उससे बाद अपराध करने पर और अधिक सजा का प्रावधान है। इस अधिनियम के अन्तर्गत शीघ्र न्याय प्रदान करने हेतु अत्याचारों के अपराधों की जांच के लिए सब न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में बनाया जाएगा। विशेष न्यायालयों में अत्याचारों के मामलों हेतु एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा। अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों को न्याय प्राप्त करने में सहायता हेतु कानूनी सहायता सहित समुचित प्रदान की जाती है। पीड़ितों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिये समितियों का गठन करने की व्यवस्था है। ये समितियां ऐसे उपायों के प्रतिपादन एवं क्रियान्वयन में सहायता देती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षा की की गई है कि वे आवश्यकतानुसार अन्य विशेष अदालतों की स्थापना करें। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरूणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर दिए हैं। राजस्थान राज्य में छह विशेष न्यायालयों का गठन अलग से किया गया है। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाए गए कदमों का समन्वय करके, स्वयं अपनी ओर से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाए गए कदमों पर एक विशेष रिपोर्ट संसद के दोनों सभा पटलों पर प्रत्येक वर्ष रखनी होती है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अपराधों/अत्याचारों को रोकने के लिए दण्डात्मक व पुनर्वास संबंध अनेक उपाय करते हुए विस्तृत दिशा निर्देश राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी किए जा चुके हैं।

[श्री सीताराम केसरी]

संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग होगा । यह आयोग बहुत जल्दी गठित किया जाएगा । इस आयोग के कार्य व्यापक होंगें । इस प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए वैधानिक और संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं । भारत सरकार अनुसूचित जातियों, जनजातियों और और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की समस्याओं के प्रति पूर्णतः सजग हैं ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर किसी भी अत्याचार की सूचना तुरन्त प्राप्त करने और राहत और सहायता उपलब्ध करने के लिए मैं शीघ्र कारवाई हेतु कल्याण विभाग (कल्याण मंत्रालय) में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ।

भारत सरकार नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 दोनों के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बराबरी के आधार पर (50:50) पर राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है । वित्तीय वर्ष 1990–91 के दौरान 5 करोड़ रुपये के कुल बजट प्रावधान में से अत्याचार अधिनियम, 1989 के अंतर्गत सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1.94 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए हैं । नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत नियुक्त की गई राशि 2.29 करोड़ रुपये थी 1991–92 के चालू वर्ष के लिए बजट प्रावधान 5.50 करोड़ रुपये हैं ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारों और उनकी सामाजिक आर्थिक दशा के बीच के संबंध को देखते हुए भारत सरकार का दृष्टिकोण उनका विकास करना और उन्हें मुख्यधारा में लाने का है । कल्याण मंत्रालय की गई केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजनायें हैं जिनका उद्देश्य इन कमजोर वर्गों का शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर विकास करना है ।

सरकार पूर्णतः सजग है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारों को रोकने के पर्याप्त उपाय होने चाहिए और उन्हें न्याय प्रदान करने के लिए शीघ्र कारवाई करनी चाहिए ।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को अपने पत्र दिनांक 31 अगस्त 1991 में देश के कई भागों में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर चिंता प्रकट की जिसमें अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा समाज के अन्य वर्गों पर अत्याचार हुए हैं । उन्होंने केन्द्रीय सरकार की तथा सभी राज्य सरकारों की समाज के इन वर्गों को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके पूरे अधिकार सुनिश्चित करने की वचनबद्धता दोहराई है । प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को यह जोर देकर कहा है कि वे व्यक्तिगतरूप से सुनिश्चित करें कि राज्य में प्रशासनिक तंत्र इस प्रकार सुदृढ़ किया जाए कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हों और यदि प्रशासन में कोई लापरवाही है, तो उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाही की जाए । प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय बाद इस प्रश्न पर सभी मुख्यमंत्रियों की एक बैठक भी बुलाने की इच्छा प्रकट की है ताकि देश भर में एक समान दृष्टिकोण अपनाया जा सके ।

श्री सत्य प्रकाश जालखोरिया (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, इस वक्तव्य के संबंध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । श्री गुरुदास दासगुप्त का कालिंग एटेंशन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर बढ़ते हुए अत्याचारों के संबंध में है । मंत्री जी ने जो स्टेटमैंट दिया है और जो तीन पेज का है उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में कहा गया है । लेकिन समाज के अन्य कमजोर वर्गों के संबंध में उसमें कोई चर्चा नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि उनके संबंध में मंत्री जी का क्या कहना है ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Mr. Minister...(*Interruptions*)... Okay.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, I am on a point of order. The women in the country constitute the largest of the weaker sections. As I understand from the wording of the calling attention the "weaker sections" include women. Therefore, I request the hon. Minister in his reply to cover the issues concerning women also.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): I am on a point of order. This relates to the procedure adopted in this House. Most of the Members have given their names for a calling attention notice but only eight names are figuring in the "List of business". The Members who have given notice for the calling attention with the very same wording, have been ignored. They have been put in the list of no-day-yet-named motion. Now this has been done. Today I received the bulletin and I have given the specific wording "including some atrocities at some places." But in the calling attention it was ignored. This may be enquired into.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Okay. I shall look into the matter. I shall request the Members to be brief and to the point.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Mr. Vice-Chairman, at the beginning let me put on record that this House has created history today by taking up the calling attention in the post-lunch period breaking all the conventions... (*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Don't make comments on the Chair.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I must put it on record. This is for the first time that the calling attention is being taken up in the post-lunch period breaking all conventions.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): It has been done with the approval of the House.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Secondly, the statement read by the hon. Minister falls short of the attention that was called because I had called the attention of the Minister not only to the atrocities committed on Scheduled Castes and Scheduled Tribes but also on weaker sections and according to me the term "weaker sections" includes the women of this country. Therefore, the statement that the hon. Minister has presented before the House is totally partial because the Government is not totally alive to the gravity of the situation.

Thirdly, the three-page statement does not anywhere clearly indicate how many instances of atrocities have taken place in the country this year or the previous year or year before that. We have been given no statistics. That is very important. I know statistics is a jugglery but that is important because it only shows to what extent the Government has been active and how many culprits have been apprehended and in how many cases exemplary punishment has been meted out to them. Therefore, this statement is inspired and reflective of the attitude of the Government towards this national problem. While going through the statement, on page 3 the hon. Minister says: "Considering the close nexus between the atrocities the SCs and STs are subjected to and their socio-economic condition, the approach of the Government of India has been to develop them and to bring them into the mainstream." The Government speaks, the Minister speaks, of the economic uplift and to what extent the dependence of this section on the rich and propertied section can be curbed. And while discussing this problem, the hon. Minister speaks of a number of measures or schemes. But he does not say how he is going to bring about a shift in the alignment of forces in the countryside. For, it is quite well known that the atrocity in the countryside takes place because the alignment of forces or balance of forces is heavily loaded against this poor, downtrodden, unprivileged, unprotected section of the society. If there is no attempt to bring about a socio-economic reform to a very large extent which will bring about a change in the alignment of forces, then, Sir, despite the schemes, despite the good wishes

[Shri Gurudas Das Gupta]

the Government may have, despite the Prime Minister meeting the Chief Ministers or despite the setting up of a national commission, the situation is not going to be altered. Therefore, in this respect too, this statement is superficial and the Government once again fails to go into the root of this social problem.

Sir, the Government, again, has not delineated the relationship between the economic status of the unprivileged and their social status, that is, their poverty their hunger, their total, dependence, their pauperism and that which makes them subject to the torture, social torture, the discrimination, in the society. Therefore, this is a statement prepared by the bureaucratic machinery who do not have any social perspective and social bias. It is precisely the same mentality of the Government which made it fail. The Government has failed not because it does not have any goodwill or intention; it has failed because it does not know how to act and where to act. This statement is only reflective of the superficial attitude of the present Government.

Sir, since the Minister has not given any statistics, for his benefit and for the benefit of the House, let me tell you this. The all-India statistics say that crime against the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, in a span of six years between 1981 to 1986, was to the extent of 1,15,055 cases. That is, more than one lakh cases of atrocity have taken place in this great country within a span of six years. This is how the dream of the Mahatma is being realised by his disciples. This is how the country has responded to the most chronic, malignant, persistent, all-pervasive social problem of the society. Only in one year, in 1989, there have been more than 14,000 cases of social atrocity. Among them, there are more than 500 cases of murder and 759 cases of rape. Helpless people are murdered and women are raped. These are the two most important characteristics of the social atrocity and outrage going on in the country. In the list of atrocities, Madhya Pradesh tops. Next to Madhya Pradesh, it is Bihar. And after that, it is U.P. and then, it is Rajasthan and the next turn is that of Andhra. Between 1988 and 1990, within a span of three years, there had been 1200 murder cases. The statistics were not quoted because it does not suit the Minister's interests, because it is a sad commentary on the performance of the successive elected Government in India, run by one party or another. This is the sad commentary of the elected Governments. That is why, maybe, the Minister has not quoted the statistics in his lengthy report. Sir, it is a matter of colossal national shame because social discrimination still persists. It is a matter of colossal national shame. (*Time Bell rings*).

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Okay. You carry on but be brief.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I would like to know as to how much time would be given to me because I have been raising the Call Attentions here. Normally, 15 to 20 minutes are allowed to the person who moves it. I have just raised the question. If you want me to sit down, I can sit down.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): You have already taken ten minutes. You take another five minutes.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I am initiating the discussion.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): You please carry on.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: The entire House should advocate that the problem of national outrage should be presented to the House so that our conscience is outraged. The social discrimination is on the rise, atrocities are galloping and I must say that the national conscience is unruffled and I must admit, on all occasions, the Government is accused of total inaction, whatever may be the colour or philosophy of the Government. Despite constitutional provision, despite enactments—one after another—despite the Government's set-

ting up special courts, despite the Government clearly indicating what should be the course of action in case of massacre or catastrophe, I am constrained to say that the atrocities are on the rise on the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the women and other weaker sections of the society. A reference to atrocities in this House has turned out more or less to be a formal affair, a ritualistic, affair. We seek to discharge our national responsibility by Parliamentary discourse but, Sir, I must say the trend goes on unabated. The massacre very recently near the place where the Prime Minister was born in Andhra, the catastrophe that took place in the constituency of the Chief Minister of Uttar Pradesh, only indicate how swollen is the mood of the caste offenders in this country. Therefore, Sir, shall we not turn to find out the root? Only a superficial statement to say to what extent the Government had been indulging in doling out money, has been bestowing privileges on the unprivileged section of the society will not solve the problem. Shall we not turn for a moment to discuss that we must act differently and not move on the dotted line, to bring about immediate and drastic change in the situation that seeks to bring the country to shame? The State machinery has proved to be inadequate. It has proved to be insipid, it has proved to be faulty, it has proved to be biased, it has proved to be heavily loaded against the unprivileged whether it is Bihar, Uttar Pradesh or Andhra or any part of the country. If social injustice is not ended if economic insecurity is not reduced and eliminated step by step, if the false sense of remedy corroding the minds of younger generation of the higher caste is not fought out ruthlessly, if the inferiority complex in the minds of the lower caste is not substituted with a sense of confidence, I am constrained to say that the social panorama in the country is not going to be altered. Sir, I implore upon the Government to take steps to increase the asset base of this unprivileged section. I request the Government to ensure that the common land in the village is not monopolised by the proprietory section. I wish the Government takes into consideration the question of supply of consumption credit to these unprivileged sections through the nationalised banking. I only implore upon the Government to find some time to discuss and study the Report of the National Commission on Rural Labour which has confronted the country with a number of facts. It is mentioned in the Report of the Commission that despite 40 years of planning the improvement in the poverty sector has been too much marginal. Therefore, I wish the Government immediately enacts Central legislations for agricultural workers dominated by the Scheduled Castes, makes welfare laws for rural workers whose number is increasing day by day in the country and with enough fundnig from the Central Government of this country.

Sir, the land concentration must be broken. Somebody might by speaking about the election manifesto of this or that paty. Since when is the Congress Party committed to the elimination of land concentration? Since when is the Congress Party committed to the abolition of untouchability? Since when is the Congress Party committed to the alleviation of social injustice? Since when is the Congress Party committed to bringing about an end to this outrage? Sir, there is always a gap between promise and practice. I don't believe it is only the Congress which is in default.

Therefore, this land concentration must be broken. Land reforms have to be carried out. The private armies raised by the zamindars in different parts of the country must be dismantled. The leaders of the law-enforcing agencies must be disciplined. There has to be an exemplary penal punishment in respect of those officers who fail to curb massacres in their own places of jurisdiction. Sir, I must say that I am against politicisation of this problem of social outrage. I want all political parties to unite. I want national consensus to be developed, I want resistance to be built up and, Sir, I must confess that it is under such a situation that the Ministers can be taken more

[Shri Gurudas Das Gupta]

seriously, it is under such a situation that the law-enforcing machinery can be forced to become more activated; without public pressure, without there being a national movement, without there being a national awareness, not only concerning and involving the unprivileged but the etire nation, the Ministers cannot be made to act, the Government cannot be forced to become alive to the situation, the law-abiding machinery cannot be activated. Therefore, I must believe this is the time to build up a national movement across political colours and affiliations. I am sorry to say that the high caste syndrome is discernible in the leadership of most of the political parties at different levels. I don't believe it is the task of the political parties only to decry the Government in this respect because political parties cannot absolve themselves of the responsibilities with regard to this grave and growng menace of social outrage in this country, but that does not mean that we shall not say that the Government has failed in all respects in this matter. We must believe that the cycle is taking a full turn. Terrorism is on the rise in the country and terrorism thrives on hatred, indignation and a sense of alienation. Terrorism—whatever may be the name, Naxalism or any other variety—thrives on a sense of alienation, on a sense of total loss of faith, on a sense of growing anger and indignation. If no method is found out by the existing social establishment of the country to solve it, the country will take too much greater violent social convulsions which this system cannot afford to endure. Sir, in conclusion, I only wish you to look at the development that is taking place across the Indian borders. What had happened in the Soviet Union? What had happened to the East European countries? What had happened in many parts of the world? If the social system is found to be inadequate to bring succour to the problem, if it fails to become the representative and embodiment of the aspirations of the people, there is bound to be greater convulsion, violent in nature, which may be against the traditions of India. But no country is going to be left out. There is a note of warning and the note of warning arises not out of the activities of the Naxalites in dfferent parts of the country. The note of warning arises out of the social development in the entire world. I believe. If nothing is found out in that case, the victimised social strata will take to arms in a much bigger way than they have been taking up. Therefore, as the guardians, the so-called guardians of Indian democracy—the Members of Parliament and the Members of the Government—have a responsibility to people. The time is running out. Today is the time, tomorrow may be too late and, therefore, it is essential that something drastic, more than some pronouncement, must be done in this regard. Therefore, at the end I would like to ask the Minister to answer a single question. The single question is not of statistics, not of statements, not of solemn declarations, but an answer to the challenge posed by the menace of social outrage.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): For the information of the Member I would like to inform that every Member can be allotted only five minutes according to the Rules and we have to complete the whole business within one hour. Therefore, I shall request the Members to be brief and to the point. Now, Mr. Murlidhar Chandrakant Bhandare.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Mr. Vice-Chairman. Sir, there is hardly any Session of Parliament when all the Members cutting across party lines do not express their anger and anguish whenever there is reporting of any incident of atrocity against Harijans or the other weaker sections of the society. There is not a single Session where many questions are not asked and if you look at the questions for the last four years, which I have brought, the answers are stereotyped. The statistics are not given any attention and very often they are wrong. There is also discussion by way of Calling

Attention or Short Duration. When I look at all these I ask myself, in anguish, whether we are not performing a mere ritual, wether we are not completing a mere formality, whether we are not rendering only lip-service to the cause which should be dearest to the heart of every Member and for which the contribution of every Member should be far more serious and sustained. Well, one of the reasons, I feel, is that we are discussing this very, very important issue—according to me the most important issue—because it reflects what our society today is. It also shows what the direction of our society is going to be tomorrow. We are discussing this issue today between 3 p.m. and 4 p.m. which is the leanest hour in the parliamentary procedure. For TV there is a prime time and for parliamentary proceedings also there is a prime time and there is this lean time. It would have sent a different message to the whole country if we had kept all our work aside and dealt with this issue on top priority.

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh): You are again raising the morning controversy.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Unfortunately it has not happened. (*Interruption*) I am on the message going to the country. I am on telling the whole world of what our commitment to this cause is. Somebody questioned the credentials, the bona fides, the commitment, of the Congressmen. Let me make it very clear that but for the Congressmen we would have been still many, many centuries behind. We should still recall what Bapu, the Father of the Nation, did. He spent most of his time living in Harijan colonies. He gave up his life for the cause of untouchability, for the redressal and removal of untouchability. And it is indeed...

SHRI MENTAY PADMANABHAM: This Congress is different from Bapu's.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: We are fortunate. In Kesriji we have a Minister who is totally committed to the poorer sections, to the weaker sections, to the downtrodden. And if he does not mend matters in his term, then in this country I don't think that any other Minister would mend the matters. (*Interruptions*) I request you Mr. Vice-Chairman, to give me two more minutes so that I can tell you detail. I don't like to take more time. But the question is so colossal and yet we are confining our discussion to oinly one hour in this session which I really cannot appreciate. We recall Article 17 which says that untouchability is abolished. And yet we find that untouchability far from being abolished, is being practised more and more and the atrocities are on the increase. We enacted as early as 1955 the Protection of Civil Rights Act to deal with the atrocities, to deal with the offences against untouchability. Well, that has not worked. In 1989 we came with the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act. We constituted special courts. We constituted special prosecutors. What has it all yielded? Has it shown even one per cent deceleration in the atrocities against the Harijans? On the contrary we find that the atrocities are on the increase. It is indeed a matter which baffles my comprehension that whenever a new Prime Minister takes office, the first thing that happens is that there are atrocities in his constituency. I still remember the atrocities in Fatehpur when V. P. Singh with all his commitment, alleged profound commitment, to the weaker sections, took office as Prime Miniser. The first thing that happened was that there were large-scale atrocities against Harijans in his own constituency. Therefore, the malaise lies deeper. I think, as has been rightly pointed out it is a question of total deprivation, it is a question of total discrimination. And let us not waste our time in blaming this Government or that Government. As has been rightly pointed out by my honourable colleague, Shri Gurudas Das Gupta, let us cut across all our party differences, let us rise as a nation, to say what society we are going to have, what Dr. Ambedkar held dearest to his cart—liberty, equality and fraternity which constitutes the core of our Constitution.

[Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare]

And every Member who comes to this House has to take that oath of allegiance to the Constitution. Is that oath purely on paper or are we going to translate it into a reality? That is the question. Therefore, I personally feel that a lot has to be done to remove this deprivation and discrimination which is at the root of atrocities. Today you find that the Harijans are economically the most depressed, they are also the most socially oppressed. I would suggest one thing. We give large loans. Today 80 per cent of the finance in any industry comes from public financial institutions. I am making this suggestion and it is up to you Mr. Minister and I wll see that it is sustained in any court of law, that the term of loan is sustained in any court of law, up to the highest court of the land, the Supreme Court. You say that you will employ a certain percentage, a well-defined percentage of the weaker sections, of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It must be mandatory that they do not get the loan if they do not discharge this obligation. Today what has happened? The Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the oppressed and the vulnerable sections get jobs only in the Government establishments. They are totally discriminated against in matters of employment outside the Government. The second aspect is accountability. We should go into the statistics to find out as to how many offenders were actually tried and how many of those charged were convicted. We should also examine whether we have competent prosecutors, whether we have special courts and such other things which are very very important. We must also promote intercaste marriages. I am all in favour of giving some incentives to the boy from the upper caste who marries a girl belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe and *vice-versa*... (*Interruptions*)...Some incentives can be given to them in the form of additional promotion, increment etc., so that the attitude of the people changes. Then we have the problem of the educated youths belonging to the Scheduled Castes and Tribes. If one looks at it, these atrocities are a systematic effort to eliminate the educated, the more talented youths, amon the Scheduled Castes and Tribes. On must make a firm commitment in this re gard. The worst and the most importan thing is—and I am sure the whole Hous will agree with me, when I say that w must point the accusing finger at ourselves If today we are in this mire, it is becaus of what the politicians have done to th system. Three things are to be kept out c politics. Unfortunately, they are on th increase after the other party came t power in 1989...(*Interruptions*)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: L the Congress party take the lead...(*I terruptions*)...

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKAI BHANDARE: Yes, we all of us can ta the lead. Criminalisation, communalis and casteism, all these three things shou be kept out of politics. It should be ma compulsory for every Member to vi at least six villages in a year as was do by Gandhiji. The spirit is to bring abo social harmony. I will end up by sayi that, today, unfortuantely, we have time to discuss other issues and the mc important of the issues is that of wom which is far more serious as this secti is the largest minorityfi constituting 48 p cent of the population. This section the society is the most vulnerable. Ev today there is an acute son preference a the girl child is neglected. I hope t Minister in his reply will deal with t aspect also. We have not been able burn *Manu smriti* as advocated by A bedkar. Let us remember his words. I not each one of us think of the caste belong to, or the community we belc to or the religion or the province, l let us think first and last as Indians. Tha you.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननी उपसभाध्यक्ष जी, श्री सीताराम केसरी ज के पास यह विभाग है, इसलिए मैं पू तरह से आश्वस्त हूं । जब तक वह इ विभाग में रहेंगे, गांधी जी ने जो कल्पन की थी अनुसूचित जाति, जनजाति लिए, उसको पूरा करेंगे । यह बात

इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राज्य सभा में केवल दो ऐसे माननीय सदस्य हैं जो गांधी टोपी का इस्तेमाल करते हैं—एक केसरी जी और दूसरे श्री रफीक आलम जी ।

महोदय, दिसम्बर, 1985 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जहां पर श्री राजीव गांधी ने अपील की थी कि पावर ब्रोकस को अपनी पार्टी से निकालेंगे, दूर रखेंगे, उस अधिवेशन की तस्वीर हम को आज तक याद है । श्री सीताराम केसरी के अलावा 1985 के कांग्रेस के उस सम्मेलन में कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं था जिसके सिर पर टोपी लगी हो । ...(व्यवधान)...

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : आप भी लगाना शुरू कर दीजिए ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : चूंकि आज विभाग श्री सीताराम केसरी जी के पास है, इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और यह जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है यह एक विषय है, जिस पर हमें, जो हमारा संकीर्ण दृष्टिकोण है या राजनीतिक मतभेद है उनसे, ऊपर उठकर के और मिलजुलकर के समाधान का प्रयास करना चाहिए क्योंकि जितनी भी शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज कमीशन की रिपोर्ट है, जो हर साल आती है, कभी-कभी दो-दो साल में, तीन-तीन साल में इकट्ठी आती है, उसमें बराबर इस ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के, उन पर अत्याचार की घटनाओं में बराबर वृद्धि हो रही है । इसलिए हमको इसका समाधान ढूंढना चाहिए ।

मान्यवर, आज ही हिंदुस्तान टाइम्स में एक संपादकीय है, जिसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और जैसा सिविल राइट्स प्रोटक्शन की चर्चा केसरी जी ने की है, जो शायद 1955 का है, तो मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा—

"A report prepared by the Vidhayak Sansad and the Nirmala Niketan College of Social Work has come with shocking revalations about Dalits being denied entry into some 80 per cent of the temples in Marathwada. Denial of access to the common well, segregation of tea shops, a virtual bar of Dalits' entry into temples and caste prejudices are rampant in many parts of the country. That such practices should be prevalent in a State which has given the nation such reformists like Mahatma Phule and Baba Saheb Ambedkar is indeed disturbing. Dalits are victims of an unequal Hindu society and in turn of economic disparities."

मेरी अपनी समझ से यह जो समस्या है इसका मूल कारण है इस देश की गरीबी, इस देश का पिछड़ापन और किसी व्यक्ति के सम्मान को इस दृष्टि से आंकना कि वह व्यक्ति किस समाज में, किस जाति में पैदा हुआ है । हमारे हिंदू समाज में यह जो जाति प्रथा है, इसके कारण मैं समझता हूं कि देश का बटवारा हुआ है और आज भी इस देश में कभी कोई टूटन की बात की जाती है । तो जाति व्यवस्था भी इसका कारण है । मेरा निवेदन यह है कि इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार को सख्ती से कदम उठाना चाहिए क्योंकि कानून तो बहुत है, यह 1989 का कानून है प्रिवेंशन आफ एट्रोसिटिज ओन शेडयूल्ड कास्टस एण्ड शड्यूल्ड ट्राइब्स, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, 1955 और हमारे संविधान में भी व्यवस्था है, लेकिन इन सारे कानूनों के रहते हुए भी आज तक हम अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर पाए ।

मान्यवर, इसी सदन में पिछले चार-पांच दिन में बराबर ऐसी घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है । इस समय मैं उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अभी पिछले वर्ष जन्मशती मना रहे थे बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर की, तो यह जो कमीशन है, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

जनजाति आयोग की रपट है अप्रैल, 1990 की, जिसे सरकार को सौंपा गया और इसका शीर्षक है– "अनुसूचित जाति तथा जनजातियों पर अत्याचार, कारण और उपाय" । उनका यह कहना है कि इस रिपोर्ट को बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर के 99वें जन्म-दिवस पर प्रस्तुत कर रहे हैं । इस रिपोर्ट से मैं उद्धरण करना चाहता हूं क्योंकि यह रिपोर्ट बिल्कुल लेटेस्ट है– "हमें यह सूचित करते हुए खेद हो रहा है कि स्वाधीनता प्राप्त होने के 43 वर्ष बाद और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अस्तित्व में आने के 35 वर्ष बाद भी अनुसूचित जाति और जनजातियों पर नियमित रूप से अत्याचार हो रहे हैं, जो कि शोचनीय स्थिति है।"

इसमें उन्होंने कुछ केसेज का सार प्रस्तुत किया है । केसेज तो उन्होंने सैकड़ों देखे, लेकिन चार-पांच केस की चर्चा की की है कि "हमारे समक्ष घोर यातना तथा हृदय-द्रावक मानव-त्रासदियों के ऐसे प्रमाण हैं, जिनमें कहीं तो एक 16 वर्ष की आदिवासी कन्या के साथ एक पुलिस-कर्मी और उसके अपराधी साथियों द्वारा बालात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई और कहीं अनुसूचित जाति के व्यक्ति की इसलिए नृशंस हत्या कर दी गई क्योंकि उसने जो पैसा उधार दिया था उसकी वापसी की मांग की थी, कहीं दस वर्ष की कन्या की एक घोर अंधविश्वासी दंपति द्वारा हत्या कर दी गई और कहीं अनुसूचित जाति के लोगों की सात सौ झोपड़ियां केवल इसलिए जला दी गयीं क्योंकि उन्होंने बाजिब मजदूरी मांगने का दुस्साहस किया ।"

तो यह जो हमारे समाज का मानस है, इस मानस को हमको जड़ से खतम करना चाहिए । मैं ज्यादा समय न लेकर केवल तीन-चार बातों की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा । केसरी जी ने जो बयान में चर्चा की है आयोग के संबंध में कि जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति जल्दी ही की जाएगी, लेकिन बहुत दिन से मांग की जा रही है कि जो आयोग है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, कंस्टीट्यूशनल स्टेट्स दिया जाए । इसके बारे में जिस पार्टी से श्री केसरी जी आते हैं, उसके चुनाव घोषणा पत्र में भी इसकी चर्चा की गई है, लेकिन आज जो वक्तव्य दिया है केसरी जी ने, उसमें इसके बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं की है और यह रिपोर्ट है–रिपोर्ट आफ कमीशन फार शैड्यूल्ड कास्ट एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स, इसमें हर साल इस बात की मांग की जाती है और उसकी रिकमेंडेशन्स हैं :—

"It is hoped that the Government of India would take note of the views expressed by Members of Parliament and take an early decision on the repeated requests and recommendations of the Commission regarding conferment of statutory status."

एक तो मैं चाहता हूं कि अगर आज ही केसरी जी इस संबंध में घोषणा नहीं कर सकते हैं तो कुछ दिनों के अंदर– एक हफ्ते के अंदर, 10 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर, आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की घोषणा उन्हें करनी चाहिए।

दूसरे, इसी आयोग ने बार-बार इस बात को कहा है कि उनके सामने जब इस प्रकार के अत्याचार की घटनाएं आती हैं, बर्बर कांड की घटनाएं आती हैं, तो तो कुछ केसिस को लेकर वे इन्वेस्टीगेट करते और उसके बाद सरकार को लिखते हैं कि इसकी सी०बी०आई० से जांच कराई जाए । लेकिन प्रदेश की सरकारें या केन्द्र सरकार ने कुछ केसिस के बारे में इनको लिखा है कि उनमें उनकी संस्तुतियों को मानती नहीं है । इसलिए इस कमीशन ने सिफारिश की है कि :—

"Such requests fell through, and the Commission found themselves in a helpless position. Therefore, the Government of India may consider empowering the Commission to refer such cases direct to CBI."

तो मेरा यह भी निवेदन है कि इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

मेरा अगला सुझाव यह है कि एक रिपोर्ट है, यह जो शेडयूल्ड कास्ट, शेडयूल्ड ट्राइब्स की कमेटी होती है, 1985 में यह विभाग गृह मंत्रालय के पास था और 1985 से भारत सरकार ने कल्याण मंत्रालय बनाया, लेकिन जो दोनों सदनों के माननीय सदस्यों की समिति है, इसने विचार-विमर्श करने के बाद अपनी 11वीं रिपोर्ट में सिफारिश की है कि जहां तक वेलफेयर का प्रश्न है, इनकी उन्नति का प्रश्न है, इनके जीवन-स्तर को उठाने का प्रश्न है, यह तो कल्याण विभाग के पास रहे लेकिन जो कानून और व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है, इसको गृह विभाग के पास स्थानान्तरित करना चाहिए और इसका उन्होंने कारण दिया है और कारण यह सुझाया है कि कल्याण विभाग मंत्रालय को गृह विभाग के पास भेजना पड़ता है, कल्याण विभाग इस संबंध में स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता है। दूसरी ओर कानून और व्यवस्था का जो प्रश्न है, राज्यों से संबंधित है। तो यह जो 11वीं रिपोर्ट है, [illegible] की सिफारिश की है, सारी चीजों में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन इन्होंने इस बात की सिफारिश की है कि :—

"The Committee would, therefore, like the Government to reconsider their decision and transfer back this subject to the Ministry of Home Affairs as soon as possible."

और सब्जेक्ट उन्होंने डिफाइन किया है, जैसी मैंने चर्चा की है वेलफेयर के लिए :—

"The Committee, therefore, recommends that implementation of welfare programmes for the socio-economic development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be dealt within the Ministry of Welfare; but as far as the subject of atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is concerned, this should be legitimately be re-entrusted to the Mistry of Home Affairs who have all the machinery for maintenance of law and order and channel of communication of orders and instructions at their command."

इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जो संसदीय समिति की यह रिपोर्ट है और उनकी जो संस्तुति है, इसकी और भी सरकार ध्यान देने की कृपा करे।

अंत में मैं यह जरूर चाहूंगा कि जब मंत्री जी अपना उत्तर दें तो समाज के जो कमजोर वर्ग हैं—महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जिनके ऊपर अत्याचार होता है, जिनके संबंध में मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में उत्तर नहीं दिया है, उनके संबंध में सरकार क्या करने जा रही है, अपने उत्तर में मंत्री जी इसको भी जोड़ दें। धन्यवाद।

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very much disappointed with the statement given by our hon. Welfare Minister because for the last ten days, both the Houses of Parliament have been rocked with news of atrocities from all over the country against SCs and STs, weaker sections, and women in particular and when the situation is so grave, this statement does not indicate any of the immediate tasks to be undertaken. Despite all the measures that the hon. Minister has narrated here and also the measures that he is going to take, these things have been going on. Not only they are continuing, but they are also increasing day by day, year by year. So that is the total result of 44 years of independence. Why is it happening? Unless this question is answered there cannot be any betterment in the social structure or social behaviour. So many colleagues have suggested that without consideration of party and other things, everybody must attend to the upliftment of the Harijans, Girijans and other weaker sections. All these preachings have been there. Why in spite of these things the atrocities are increasing? That question must be answered. Not that there were not such preachings earlier. We have been preached Sarvodaya by Mahatmaji, Socialist pattern of society by Nehruji and Socialism by Indraji, and 'Garibi Hatao' is there. Harijan and Girijan

[Shri Moturu Hanumantha Rao]

upliftment is always attended to and everybody is so seriously concerned about it, according to their words. Despite all these things why is the situation worsening day by day? That should be answered. The national movement was aspiring for a casteless society. Now, caste wars are taking place throughout the country, and particularly in certain areas. Why all these things? It is because oppression is going on. The basic root of all these things seems to be economic oppression. Social and economic oppression is there. And the hon. Minister has not spoken of it, except mentioning it in one place. Nowhere has he said what economic measures are to be taken. The economic measures that were proposed all through these years and decades had been land reforms, tenancy reforms and minimum wage to the agricultural labour. I am speaking of these measures because most of the SC, ST and backward class people come from the landless, agricultural pool. That being so, unless their economic condition is bettered, we cannot see them develop their own social status also. Compulsory education is not attended to as it was required by the Constitution. No compulsory free education is there and no land reform is seriously implemented. Tenancy laws are just bypassed by so many methods and minimum wage is there only on the Statute Book, without getting implemented anywhere in States, except in West Bengal, Kerala and some other places, where they are seriously attended to. The point here is that we can say that everybody is concerned, every party speaks in terms of getting rid of these atrocities. But whose responsibility is it? For the last 44 years who was ruling? Why have these things developed? That should be asked. Otherwise where is the meaning in sharing responsibility? All of us can share the responsibility because we come from the same society. But is it so? Who is ruling? Why did they not attend to land reforms? Why did they not better the economic condition of these poor people? That is the question. Why in West Bengal it is not there so much... *(Time Bell rings)* In West Bengal the tenancy reform is there, land distribution has been there and minimum wage policy is implemented. That is why atrocities on these oppressed castes have not been so much spoken of in West Bengal. Why in other States—vested interests come in the way? Various parties are saying today that all these laws are not properly implemented.

4.00 P.M.

That is the main point. That is axactly why the landlords interested in a particular party see to it that the agricultural labour or poor people from their own village do not come up to their standard; that is the vested interest. They are preventing all laws from being implemented because police officers are in their hands. Police officers are not touched even if they misbehave. For instance, in Chundur about 15 persons were massacred by the village landlords or at their instance and policemen were also conniving with them. The main persons responsible for it, the circle-inspector and the sub-inspector who are named by all parties, and suspended by the Government are to be brought to book. They must be prosecuted. That is not done. One MLA is on hunger strike for it. So many people are agitating for it. All these things I have mentioned not because I am against some party; all parties are coming together and seeing to it that things are ameliorated. That is not the point. The point is whose vested interest is protecting those people who are committing atrocities against women, against SCs, STs, and other backward classes.

*DR. N. THULASI REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman Sir, there is a proverb in Telugu which literally means——'The treatment further complicated the disease'. The reactions of the Government, Parliamentarians, Political Parties, Legislative Assemblies, the Press and Intellectuals regarding the atrocities on backward communities and weaker sections are only agravating the situation. The atrocities in our country are increasing day by

*English translation of the original speech delivered in Telugu.

day like the soaring prices of essential commodities. From Kashmir to Kanyakumari, incidents of atrocities on weaker sections are taking place everyday somewhere or the other.

Previously these incidents of atrocities were limited to the States of Uttar Pradesh and Bihar only, but now they have spread all over the country. Lately in Andhra Pradesh the incidents of atrocities on weaker sections have increased. Very recently an incident took place in Chundur, previously in Badai Gadda, then in Nagaori, then in Atmakur and so on and so forth the atrocities are increasing day by day. In Kamareddy and Narayanaker even in hostels for Harijan and Scheduled caste girls incidents of atrocities are taking place and are increasing day by day. This is a matter of concern. These incidents are taking place because of the powerful political personalities in collusion with the caretakers of the hostels. I request the Government to take necessary action against these atrocities on young girls.

Sir, what we see is only the tip of the ice-berg. In fact the situation is far more serious. We come to know of very few incidents. Even after forty four years of independence our dream of social, political and economic equality remains a mirage. We could not achieve the goals of Mahatma Gandhi.

In villages feudal system is not only existing but increasing. The life in villages is becoming hectic.

Sir, we are not able to understand and implement rich Indian Culture and traditions. We all consider Ramayan and Mahabharat as sacred documents and appreciate the characters. But then we are not able to understand the basic principles of these puranas and the purpose of these different characters. What does Mahabharat say? It encouraged inter-caste marriages. Sage, Vashisht, being a Brahmin married Arundhati, a Scheduled caste lady. This couple gave birth to Shakti. Shakti and Chandalagi gave birth to Parashara. Parashara and Matsya Kanya gave birth to Vyasa who begot Dhritarashtra through Ambika, and Pandu through Ambalika and Vidur through a maid-servant. Sons of Dhritarashtra were called as Kauravas and those of Pandu, Pandavas. In brief this is all about Mahabharat. Inter-caste marriage were encouraged right from the days of Mahabharat which we accept as a sacred document. Who wrote Ramayan? Valmiki, who belonged to a Scheduled Tribe.

The great poet Vemana says—'People consider a person who eats the beef as a Harijan but do they thing that all those who eat Chieken and Pork are saints'? So, many things were said but still there is no change in our attitudes.

Sir, these days a new consciousness is growing among these weaker sections. But the feudal forces are not able to digest this new awakening in them. So They are trying their best to suppress this awareness in them. But their efforts will prove futile as it is difficult to stop the sun light with the help of a hand. But Sir, as I mention about this consciousness among the weaker sections, I would like to remind the Government about an important aspect. This consciousness in same cases is being destructive also. The incident occurred in Chundur is an example of this. Both the awareness of the weaker sections and the power of the fedual forces are clearly known by this incident. Massacre of eight innocent Harians is an example of the atrocities of feudal forces, and Harijans teasing young girls is an example of their destructive awareness. Both these acts are to be condemned.

Sir, as Shri K. G. Satya Murty, convenor of an organisation named 'Samajik Viplav Vedica' says, instead of treating this social problem as a caste problem it should be tackled in such a way that we should be able to remove the caste feelings among the citizens. I request the Government, all Political Partices and intellectuals, to work unitedly in solving this problem.

Thank you.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, it is again an old tale that I am to tell here from the European history of the 18th century. Poland, now very much in the news of different counts, was partitioned among the States of the time, Prussia, Austria and Russia. The then ruler of Austria, Maria Theresa used to weep for Poland, and it is said, the more she would weep here, the more took. Our position is more or less like that. The more we weep here, the more are the atrocities throughout the country.

[The Vice-Chairman (Shri Satya Prakash Malaviya in the Chair]

Atrocities are on the increase: these have not decreased, in spite of so many questions, so many calling attention discussions. The question is, whether we could really reach the heart of the problem. I remember the saying of Dr. Ram Manohar Lohia without being a Lohiaite; a Lohiaite is in the Chair at the moment. Dr. Lohia used to say that in India, caste dissolves into class. We could not agree to it. But there is a sub-stratum of truth in what he said. In fact, in reality, the lower-caste people usually are downtrodden and all the upper-caste people are not exploited. Most of the exploiters are the upper-caste people. That is a fact which has to be recognised. But on that basis, the problem cannot be resolved. I know, the Minister does not prepare the statement. It is his department which prepares it. But even then, it would have helped us if there had been some analysis as to the background of, say, a number of typical conflicts: conflicts generated by what intentions? What were the issues involved? The initiator of the discussion, Comrade Shri Gurudas Das Gupta raised the question of land reforms, the absence of land reforms in most parts of the country. Together with this, people who were so long downtrodden all these years are trying to assert themselves and they are facing aggressively the land owners, land holders, land benamdars and their combinations. The most dangerous part is that there is a collusion beween these groups and the law enforcement machinery, even the administrative machinery on caste lines. When it is a communal riot, it is on communal basis. When it is a caste riot, it is on caste basis. It is a very peculiar position prevailing in our country. Just by elopuence, we won't be able to put an end to these atrocities. It requires something more, a greater determination. It is not a question of not trying to politicise. We are all political people here. Some objection was taken to the use of the word 'hypocrisy' by the Information Minister while replying before lunch to one of the points. But the question is, if we are not individually hypocrites in our political position, in our political programme and in our political formulations, hypocricy is very much evident whether on that side or on this side. None is completely immune from it. But most of all, the ruling party at the Centre will have to bear the brunt of it. The Minister has given the information that 50 per cent of the expenses required to run the Special Courts or for raising of the forces to prevent atrocities on weaker sections of the country is borne by the Centre. Is that enough? What else has to be done? The question was raised, one or two days back, whether in case of protection to these weaker sections of the society, the Centre should not take some additional responsibilities. The question has not been dealt with here in this statement. We have been told—the staatement concludes with that—that the Prime Minister did these things and that the Prime Minister will meet the Chief Ministers. The Chief Ministers' meting with the Prime Minister is something routine. A routine approach won't solve the problem. Even a reference to Bapu won't solve the problem. Bapu could not remove untouchability from the face of our country. Bapu, no doubt, lived in poverty. But Sarojini Naidu said at that time that Bapu did not know what it cost the nation to keep him in poverty. Untouchability could not be removed. He did not consider the caste aspect an all that. Taking all these facts into account, we have to evolve a viable programme of

action if really it is our resolve to do
action if really it is our resolve to do

श्रीमती सुषमा स्वराज : (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, जब से इस सदन का सत्र शुरु हुआ है, शायद ही कोई दिन ऐसा बीता हो जिस दिन समाज के कमजोर तबके से संबंधित किसी एक वर्ग पर होने वाले अत्याचार की शर्मनाक और दर्दनाक दास्तान इस सदन में न सुनाई गई हो । कोई भी एक सदस्य किसी खौफनाक और दिल दहलाने वाली घटना का उल्लेख करता है तो उसके बाद सदन के सारे सदस्य समेत पीठासीन सभापति के अपने आप को उससे सम्बद्ध करते हुए उस घटना पर चिन्ता व्यक्त करते हैं और उसके बाद सरकार की ओर से रटा-रटाया जवाब आ जाता है कि तथ्य इकट्ठे किये जा रहे हैं और जब तथ्य इकट्ठे हो जायेंगे तो सदन को सूचित कर दिया जाएगा । यह सिलसिला एक रस्म बन करके रह गया है । इस रस्म-अदायगी के दायरे से सरकार को बाहर निकाला जाये, सरकार की ओर से किसी ठोस कार्यवाही का आश्वासन प्राप्त किया जाये, इस उद्देश्य से हमारे सदन के कुछ साथी सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय के तौर पर इस विषय को उठाना चाहा । लेकिन अफसोस इस बात का कि जिस गम्भीरता की अपेक्षा हमने सरकार से की थी उस अपेक्षित गम्भीरता से सरकार ने आज भी इस विषय को नहीं लिया है । मंत्री जी का वक्तव्य देखने के बाद हमें निराशा ही हाथ लगी है । उस निराशा के तीन प्रमुख कारण हैं । पहला कारण तो यह है कि अगर यह जवाब कल्याण मंत्रालय के बजाय गृह मंत्रालय से आता तो ज्यादा उपयोगी होता क्योंकि कमजोर वर्गों से संबंधित विकास और कल्याणकारी योजनायें तो कल्याण मंत्रालय बहुत खूबसूरती से कार्यान्वित कर सकता है, लेकिन कमजोर वर्गों पर होने वाले अत्याचारों से संबंधित कार्यवाही कल्याण मंत्रालय की परिधि में उतनी नहीं आती है जितनी गृह मंत्रालय के दायरे में आती है । गृह मंत्रालय की ओर से खबर आती तो जैसा श्री गुरुदास दासगुप्त जी चाह रहे थे, कुछ आंकड़े आते और कार्यवाही का कोई ब्यौरा आता । यह मेरी निराशा का पहला कारण है और दूसरा निराशा का कारण यह है कि कल्याण मंत्री जी ने जो यह वक्तव्य दिया है, यह एक अधकचरा दस्तावेज है । यह विषय जिसकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, इसका दायरा बड़ा व्यापक था । इसमें बड़ी स्पष्टता से लिखा गया है कि अनुसूचित जातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर बढ़ते हुए अत्याचारों तथा उसके संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की ओर हम मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं । लेकिन लगता है कि उन्होंने अन्य कमजोर वर्गों में केवल जनजातियों को जाना है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के ऊपर होने वाले अत्याचारों के बारे में ही दस्तावेज रखा है । मैं कहना चाहूंगी कि जिसके सामने हम अत्याचारों का रोना रोना चाहें रहे थे वह स्वयं अत्याचार करने वालों में सरीक हो गये हैं । जिस मंत्री से अपेक्षा थी कि वे महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों के संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा देंगे उन मंत्री महोदय हैं स्वयं महिलाओं की इतनी उपेक्षा की है कि उनके तीन पेज के दस्तावेज में एक वाक्य तो दूर की बात, एक शब्द भी महिलाओं के लिए नहीं है । वाक्य तो पांच-छः शब्दों से मिलकर बनता है। इसमें एक शब्द तक महिलाओं के बारे में नहीं लिखा गया है । यह मेरी निराशा का दूसरा कारण है । मेरी निराशा का तीसरा कारण वही है जिसकी ओर माननीय एम०सी० भंडारे जी ने भी इंगित किया है और वह समय की एलाटमेंट के संबंध में है । अच्छा होता अगर भंडारे जी सुबह उपस्थित होते तो अपनी ओर के साथियों को समझा सकते थे । आज सुबह आप नहीं थे । मैंने आज सुबह नियमों के अधीन इसको उठाया था । जो प्राइम टाइम की बात आपने कही है वह वाकई बड़ी अहम बात है । लेकिन अगर आज सुबह होते तो अपनी ओर के साथियों को समझा सकते थे । यह एक ऐसा विषय जिसको अगर नियम नहीं भी होते तो भी तमाम चीजों को छोड़कर इस विषय को प्राथमिकता देनी चाहिए

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

थी । लेकिन यहां नियम इस बात का उपबन्ध करते हैं, इस बात की व्यवस्था करते हैं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बाकी अमाम चीजों को छोड़कर लिया जाएगा। मगर आज इस हाउस की सहमति की आड़ लेकर नियमों की अनदेखी की गई और दोपहर के बाद, जैसा आपने कहा, तीन टाइम मेंइसको लिया जा रहा है । मेरी निराशा के ये तीन प्रमुख कारण हैं। उपसभाध्यक्ष जी जहां तक इस तरह की घटनाओं का ताल्लुक है, इस तरह की घटनायें एक ओर तो शासन और प्रशासन की ढिलाई को उजागर करती हैं और दूसरी ओर समाज में फैली हुई संवेदन-होनता का पर्दाफाश करती हैं । संविधान के द्वारा प्रदत्त समानता के अधकार को मौलिक अधिकार की सूची में डाल दिये जाने के बावजूद आज भी क्या यह सच नहीं है हमारे दलित भाई, अनुसूचित जाति के बंधु अस्पृश्यता का शिकार होते हैं ? छुआछूत का जहर उन्हें आज भी पीना पड़ता है । मंत्री महोदय ने अपना दस्तावेज शुरु करते हुए कहा कि सरकार अस्पृश्यता से पैदा हुई किसी भी असक्षमता पर दंड की आवश्यकता को स्वीकार करती है और इसके लिये नागरिक संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया है, जिसके तहत दंड का प्रावधान किया गया है । मंत्री जी, मैं आपका लंबी-चौड़ी पुरानी नहीं, केवल कल के टाइम्स आफ इंडिया में छपी एक खबर की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी है जिसका कैप्शन है

'Dalits denied temple entry in Marathwada'.

खबर बहुत लंबी है । केवल पहली चार लाइनें को ही सदन के सदस्यों और आपकी जानकारी के लिये पढ़ना चाहूंगी ।

"Bombay, September 2. Dalits are being denied entry into 80 per cent of the temples in Marathwada. This shocking statistic has been revealed in a report prepared by Vidhayak Sansad, a Vasai-based organisation working for rural upliftment and Nirmala Niketan College of Social Work, that was made available to this newspaper."

मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि दंड का प्रावधान है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम आपने अधिनियमित भी कर दिया है, लेकिन क्या मराठवाड़ा को इसकी परिधि से बाहर रखा गया है ? अधिनियम के रहते हुए भी, अस्पृश्यता और छुआछूत के लिये दंड का प्रावधान होने पर भी मराठवाड़ा में 80 फीसदी मंदिरों में हरिजनों का प्रवेश निषिद्ध है । क्या हिन्दुस्तान के कल्याण मंत्रालय की जानकारी में यह बात नहीं है ? अगर उसकी जानकारी में यह बात है तो इसको अनदेखा क्यों किया गया है ? दलितों का प्रवेश आज भी वहां क्यों निषिद्ध है, इसका जवाब मैं मंत्री महोदय से चाहूंगी ।

उपसभाध्यक्ष जी, केवल यही नहीं, जाति प्रथा के आधार पर किये जाने वाले भेदभाव को संविधान की अवधानना मानी जाती है । लेकिन आज से आठ दिन पहले यही, इसी सदन के अंदर आन्ध्रा-प्रदेश का किस्सा रखा गया । यहां पर मुतम्मा को निर्वस्त्र करके बाजार में घुमाया गया । महोदय, इस जड़ में केवल यही जाति प्रथा है । यहां पर तथाकथित उच्च जाति की कही जाने वाली लड़की ने एक पिछड़े वर्ग के लड़के के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा । इस पर वहां के उच्च जाति के लोगों ने उस मुतम्मा को यह कहकर कि उसने उस लड़के को भगाने का अपराध किया है, उसको निर्वस्त्र करके पूरे बाजार में घुमाया । मैं कहना चाहती हूं कि यह कुकर्म तो केवल कुछ लोग करते हैं । लेकिन समाज का बाकी वर्ग जो मूक दर्शक खड़ा रहता है, उनके लिये भी मंत्री जी क्या आपने कोई दंड का प्रावधान रखा है ? कुकर्म करने वालों के लिये कम से कम दंड का प्रावधान तो है । अगर कभी कोई अधिकारी कानून की पालना करने वाला वहां होगा तो शायद इसके तहत एक आध कुकर्मी दंडित भी हो जाये लेकिन वे लोग जो एबेटमेंट

का अपराध करते हैं, बाजार में खड़े होकर मूक दर्शक बनकर उस महिला को निर्वस्त्र देखते रहे, महाभारत की द्रौपदी के चीर हरण पर हम लोग आंखें शर्म से झुकाते हैं, लेकिन आज के आजाद भारत में आजादी के 44 साल के बाद भी यहां पर सैकड़ों द्रोपदियों का चीर-हरण बाजारों में, मोहल्लों में और शहरों में किया जाता है, बस्तियों में किया जाता है । मैं पूछना चाहती हूं कि उन मूक दर्शक रहे दर्शनार्थियों के लिये आपने दंड का कौन सा प्रावधान किया है ? इसलिये इस समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते समय मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि क्या कोई सामूहिक जुर्माना जैसा प्रावधान आप करेंगे ताकि वे एबेटमेंट करने वाले जो स्वयं कुकर्म तो नहीं करते लेकिन मूक दर्शक बनकर देखते हैं, वे ऐसी चीजों का विरोध कर सकें । जिस गांव में, या बस्ती में हरिजनों पर सामूहिक अत्याचार हों, बस्ती को उजाड़ा जाता हो, सामूहिक बलात्कार किया जाता है या उनकी झुग्गी-झोपड़ियों को जलाया जाता हो उन गांवों में जो सरकारी सुविधायें उपलब्ध हैं, जो उनको मुहैय्या कराई जाती है उस पर सरकार क्या रोक लगाने के बारे में विचार करेगी कि अगर आपके गांव में इस तरह की घटना होगी तो आपको ये सुविधायें नहीं दी जायेंगी ? क्या सरकार समाज के कमजोर तबकों को जिनमें महिलायें भी शामिल हैं, अगर वे अपनी आत्म रक्षा के लिये हथियारों के लाइसेंस देने के लिये आयें तो क्या इस संबंध में उदारता की नीति आप इन कमजोर वर्गों के लिये अपनायेंगे ताकि अपनी सुरक्षा के लिये वे हथियार प्राप्त कर सकें ? क्या इन लोगों को जो दंगा पीड़ित इस तरह से हो जाते हैं उनके पुनर्वास के लिये जो रस्मी चीज चल पड़ी है कि दो हजार रुपया राहत के रूप में दे दिये जाएं और उस दो हजार रुपये की अब रुपये का अवमूल्यन होने के बाद केवल पांच सौ रुपये कीमत रह गई है, तो क्या इस राहत के अंदर कुछ और बढ़ोत्तरी करने की बात आप करेंगे ? यही तीन सवाल पूछते हुए मैं इस समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं ।

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR (Nominated): Mr. Vice-Chairman, there are two incidents that have already been discussed in the House. One is related to the Mathura incident, and the other incident is related to Tsundur. Both are poles apart. I I am saying that they are poles apart because one was an incident where the case structure of this country was being sought to be destroyed, and in the other place namely Tsundur, it was a caste war. In these two incidents, I have submitted last time that we have to make a differentiation. What we normally do is that we treat all these cases similarly under the Indian Penal Code without making any distinction. If we look minutely at the Mathura incident, the form of torture that went on, reflects some of the laws that were enacted in the Manusmriti. In the Mathura incident somt of the private parts of both the boy and the girl, before they were hanged, were cut off. In the Tsundur incident, those who were of the age of 15-35 years and those who were educated, were slaughtered.

Let me put the case of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, how they look at this matter. They have been thinking that with the Poona Pact, the atrocities and discrimination against them might be stopped. But, even after the Poona Pact and even after 40 years of independence, me have not been able to eradicate the social inequalities that exist in the society.

I will come to the attitude part of the Government. Here we are discussing the incidents, and a message has to be sent to our countrymen. I do not believe that people are going to change by themselves because here we have a society which is graded with equality, and in this system which is graded with eqality, people who live in the upper structure are not going to leave their higher position for the sake of the lower people. It is here that the question of the message comes that the Government and the administration at whatever cost

[Shri Prakash Yashwant Ambedkar]

is ready to bring about equality in this country. Had it been that case, had there been that attitude of the Government, it would have given precedence to this subject which we are discussing now, over and above the reply that was supposed to be given by the Minister of Communciations. It is the attitude to which I am coming back over here. Until and unless the Government has its own attitude, untill and unless the Government spells out its own attitude towards this problem, I don't think we will solve this problem.

I will come to another aspect which is over here. I will say that we have divided the society by calling one section of the society "Harijans" and the other section of the society "non-Harijans". We ourselves, by our attitude, by our deeds, have made differentiation in the society. If we want to bring about equality, my first demand before the hon. Minister is to see that the word that has been used in this House and outside this House, calling them "Harijans" which will segregate the people, should be first of all stopped.

It will give a positive message to the masses. I would not stick up to the ideological aspect of it as to what ideologies it carries, but I would only say that this segragation that we have made, of the masses, has first to be stopped. That, I think, will be a positive message. The Minister may kindly think over it.

The next aspect is about the general attitude the Scheduled Caste and Scheduled Tribe representatives face. I am not politicising or criticising any of the Scheduled Caste Member of this august House, but the system in which they are really placed in is different from what it obtained earlier. Earlier the Scheduled Caste and Scheduled Tribe reserved seats were contested such that non-scheduled Caste and non-Scheduled Tribe people did not take part in voting. Therefore, they had some kind of proper representation from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But of late even the non-Scheduled Castes are taking part in voting. By this system the Scheduled Caste representatives, who come to Parliament, are controlled by the high caste Hindus because with their votes he has been elected. There is a fear in such representative that if he does not discharge his duties towards the high-caste Hindus, he would not be elected next time. Therefore, a demand is gaining ground outside Parliament that such a system has not given any justice to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Therefore, we must again revert to the earlier system of electing our representatives from the Scheduled Caste and Scheduled Tribe voters only.

I hope the Minister will think over it.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will you yield for a minute? This is a very important point. Do you really feel that this philosophy of equal but separate will lead you anywhere?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): That is his opinion.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: As far as the social structure of this country goes, we might believe in the slogan of diversity in unity, but let me put it that, if the diversities are there, we have to recognise them. Then only we can tell the people that these are the diversities and these are the issues on which we have to unite. This is my philosophy.

SHRI PRAMOD MAHAJAN (Maharashtra): You go by any process, the number will be same.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: The next point that I would refer to is the 1989 Act that has been passed. There are many departments which do not know whether this Act is in existance. There are many police stations which do not know that such an Act has been passed. I would refer to the Parbani incident where a Scheduled Caste was killed in a temple. When we asked the police officer to register the case under the IPC and also under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes

(Prevention of Atrocities) Act, 1989, the police officer said there is no such Act. I will produce a letter from the Human Rights organisation, Maharashtra, which has written to the Police Officer stating that they were supplying him a copy of the Act.

The Minister has said that he is extending nearly Rs. 5.5 crores for the implementation of the Act. Speaking for my State, I would say right from the year 1986 till today, not a single Naya Paisaa has come from the Central Government as part of the 50 per cent grant for the implementation of the Act. The last point that I will make over here is under the 1989 Act, all the Government officials who are responsible for not taking action should be punished. Even after the 1989 Act was passed, there is not a single case in which we can say that on account of lapse on the part of the Government official he has been punished. (*Time bell rings*) I am concluding. Till today we were hearing the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been at the receiving end. But after the Tsundur incident we find that there is retaliation. This theory of retaliation in now gaining ground among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. You have already got enough problems in your hand. The atrocities which are taking place against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are no doubt a social aspect. But along with social aspect there is a change in the economic condition also. If we can reduce the economic inequality of this community, I think, we can control the situtation. If not we will be drifting away from it and will be having new problems on our hands. With these words, I thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Hon. Members, the time is running out of hand. You shall have to be brief. I repeatedly request the Members to abide by the time. Shri Arangil Sreedharan.

SHRI ARANGIL SREEDHARAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, anger and agony swell in my heart when I rise to participate in this debate. I feel angry because of the atrocities perpetrated on Harijans, Adivasis and women. I feel agony because of the helpless situation in which our democratic state is placed. The hon. Minister's statement has catalogued a number of steps that are being taken to prevent atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But it is obvious that these steps have not succeeded. It is not the first time that the Government comes before the House and enumerates the steps taken by them. Even during the freedom struggle the Father of the Nation fought for amelioration of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and women. In one of his statement he said "A *bhangi* girl should become the President of India." That was the vision he placed before this country. In spite of 44 years of freedom, the atrocities against Harijans and women are going on without any let or hindrance. Why this is happening? Is it because we don't have the police courts? Is it because we don't have the police force? Is it because we don't have the machinery to enforce the law and order? All these things are there. The long arm of the law is there. The forces of the Government are there. All the resources are there, yet we have not improved the lot of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and we have not improved the lot of women. I think it is largely because we have to look at the structure of the Hindu Society. The structure has not changed. The vast majority of the Hindu society are enclosed in caste. They are born in caste. They marry in caste and they die in caste. We have not been able to change the situation at all. Several reformers came but this caste system has defeated all the reformers. And after Independence, the rigidity of castes, the cruelty of castes, the diabolical ruthlessness of castes has increased. If it has increased, what do we do? What is the picture before us in the Indian society? What is the picture of a Hindu girl before the Indian society. The picture of a Hindu girl is a meek Sita or a helpless Savitri. How can women be liberated in this country? A few months ago, if I remember rightly, 'Sati' was glorified in this country.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): Still it is glorified.

SHRI ARANGIL SREEDHARAN: I wanted to be sure of my statement. I stand corrected. If that is so, even today, 'Sati' is performed and it is glorified in this country.

Sir, in this country, violence against women is perpetrated even before they are born. When, through experiments, they come to know that a female child is going to be born, the female foetus is destroyed. It does not at all happen in any other country. The dowry system a cruel system, is the reason. Have we been able to control the dowry system. Even in the affluent society, educated society, it is prevalent. I come from the State where women are in a majority. I come from the State where female education is the highest in the country. Even there, the dowry system is prevalent. We have not been able to stop it. We have not been able to control it. The dowry system cannot be controlled. What happened recently? A 11-year girl was married to somebody from a Gulf country. The system was going on for some time in my own State. We used to call it 'Arab Marriage'. Why do these things take place in this country? Why is there no liberation of women? Why is there no liberation of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes?

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: With your permission, I want to add this. I salute this gentleman. . . . . .

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAKIA): Hon. Member.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: .....for speaking with that agony in his voice on behalf of us, women. I am just drawing your attention to an incident on 2nd September. The Warden of a girls hostel in Kamareddy in Nizamabad district of Andhra Pradesh has confessed to have sexually assaulted three hostel inmates of whom one was found to be pregnant. This for your record. Those girls were minors. They were threatened with expulsion from the college where they were studying. The poor girls went there in the name of education. Law and order is a State subject. But this has to do not just with the State. This has to do with us as women collectively. It cuts across party lines. I thank my hon. colleague for his very honourable intention of drawing attention to such things. I wanted to strengthen his hands with this information.

SHRI ARANGIL SREEDHARAN: I thank hon. Shrimati Chakravarty.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Chowdhury.

SHRI ARANGIL SREEDHARAN: I am sorry. It is a serious mistake. I withdraw that and I apologise. (*Interruptions*)

That is the situation of women in our country. And all these years of freedom have not been able to make an impact on the society. We are talking of backward communities; we are talking of forward communities; we are talking of so many things. Dr. Ram Manohar Lohia, when he was alive, once said that all women in India should be treated as backward. Whether they are Nair girls or Harijan girls or Brahmin girls, they are backward. The society has been oppressing them for centuries. And if you don't take steps to educate them, your society will not develop.

Sir, I will finish within two minutes. Coming to Adivasis and Harijans, I am very proud to say that the one State in the Union where there is the least atrocity on Harijans and Adivasis is Kerala. Why? It is because of three factors. One is, land reform. Land reform came to Kerala as back as in 1961. The second is a very powerful leftist trade-union movement which will defend the backward, the oppressed and the suppressed. It is not possible to attack a Harijan family in Kerala, not because they are strong, not because the police force is strong, but it is because of the powerful political movement there that all parties are united on this issue. That is a great victory as far as my State is concerned. So what I suggest is that Harijans and Adivasis are very backward. I know the Government's financial position is very precarious. However, I would suggest to the Minister that one boy or a girl of an Adivasi or Harijan family should be adopted by the Government and the education of that boy and

girl should be at the Government expenditure and till they take up a job or get usefully settled in life, everything should be met by the Government. In that way, in the family you will create a new base and understanding of the whole thing. These things, I believe cannot be done by the Government alone. These things can be done by social organisations and political discussions. The Prime Minister of India convened a conference of the State Chief Ministers to consider the problem of the Scheduled Castes and the Scheluled Tribes. these things are not done. Governments to convene a conference of the State Chief Ministers to consider the problem of women, their backwardness and the sufferings they have. It is not merely a compartmentalised problem. The social backwardness of India has to be part of the religious level, has to be part of the economic level and has to be part of the social level. It should be an all-round effort to raise them from their present stage of derivation and degradation. I warn the Government, if these things are not done. Government's may come and Governments may go and whatever may be the political character of the Government, if this continues, then that day is not distant when these people will rise in revolt and that tornado will come and strike you. Then only you will open your eyes. Thank you.

SHRI SHABBIR AHMED SALARIA (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman, Sir, today we are discussing a very important question with regard to the atrocities on the weaker sections and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. The statement made by the Minister is incomplete and has made no reference to the women and the weaker sections such as the minorities and the children who are also suffering and groaning in the present system. The reason should be found as to why the caste system is in force in our country and so long as caste system is there, can the lot of the Harijans be improved? I feel the main reason why the Harijans are suffering is the caste system and the caste system finds place in the religion. So long as it is ingrained in religion and in the minds of the general public, we cannot get rid of it and they are treated as something less than human beings. Education is needed to given right from the inception in such a manner that in the minds of the people, the poison of casteism is removed. That will take a long time. Fifty years which we have spent since independence, in that, our educational policy was not directed towards this. Mr. Kesri may take care of it and he may talk to the Education Department and to those who have to make the educational policy of this country that the only way to save the Harijans of our country is to remove the rancour of casteism which is present in the minds of the people. Now, so far as women are concerned, for centuries they were deprived of civil rights to inherit property. Even now Mr. Kesri may get into touch with the Law Department of the Government of India and see whether or not in coparcener property the woman has still no right so far as Hindus are concerned and he may also please see whether the Harijans, are properly represented because an important question has been raised today that he who is elected on a Scheduled Caste ticket—Mr. Kesri may kindly be careful to consider this—on a Scheduled Caste ticket he is generally elected by the votes, other than the Scheduled Castes. And it is now contended that he does not represent the Scheduled Castes. If we have to win the confidence of the Scheduld Castes, I think the suggestion made by Shri Ambedkar deserves consideration. These are basic issue which have to be resolved by careful attention and by deep thought. Thirdly, I will submit that in order to better the lot of the Harijans, the weaker sections of the society the present economic system in which most of the land is owned by some and others are serfs on the land which is also one of the reasons why atrocities on these sections of the community take place —they are generally landless labourers—, do away with the landlordism, leave very little land except that which is tilled by the landlords. Don't leave so much of land with the landlords that they can have serfdom in India. Unless and until that serfdom is done away with, unless and until that fiefdom is done away with, the lot of the rural people cannot be improved.

[Shri Shabbir Ahmed Safaria]

I would like to submit one more thing. How many of us are today prepared in the Hindu society to inter-marry with those who belong to lower castes? How many of us in the general public are prepared to interdine with them or to mix with them freely? This shows that this malady is very deep-rooted and it will take a long time to remove this totally. The earlier the hon. Minister starts introducing new policies in the educational department and new reforms in the agricultural system of the country, the better it is. Then these people suffer because they have no part in the present power-structure as Mr. V. P. Singh has said. There is truth in that. The present power-structure is such that they are kept out of power. Unless and until they are made sharers in power, their lot cannot be improved. How long will they continue to be beggars? Unless and until they are given a share inpower on some method evolved by a consensus, their lot cannot be improved. With these words, I conclude. Thank you.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, इस माननीय सदन में अनुसूचित जाति, जनजाति और दूसरे कमजोर वर्गों के प्रति होने वाले अन्याय के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आज जो चर्चा हो रही है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । यह एक राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है । चर्चा के दौरान जैसी की सदन के समक्ष सारी बातें आ रही हैं, उनसे एक बात स्पष्ट हो रही है और जो सही भी है कि इसमें हम सब लोगों को पार्टी-लाइन से ऊपर उठकर सोचने का काम करना है तभी जाकर के देश के ऐसे समाज के लोगों को यह संदेश मिल सकेगा कि सचमुच में जो देश की सर्वोच्च संस्था है सदन, उस सदन में कितनी गंभीरता के साथ इस प्रश्न पर विचार किया गया है ।

महोदय, पिछले दिनों देश के कोने-कोने में इन जातियों के लोगों के साथ जो घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं के आधार पर इस तरह के प्रस्ताव पर आज चर्चा करने की बात आई है । जब यह प्रश्न हमारे सामने आया है तो महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार भी उससे संबंधित हैं । अभी कल ही इसी सदन में अलीगढ़ की एक महिला की बात आई कि अलीगढ़ जिले के मरौना गांव में यह महिला अपने खेत में काम कर रही थी और काम करते समय उसका अपहरण कर लिया गया, छह दिन तक गुप्त रखा गया, उसके साथ बलात्कार भी किया गया, यह बात भी सदन में आई । उसके पहले भी जिस तरह से मराठवाड़ा में एक अनुसूचित जाति का सब-इंस्पेक्टर वर्षा से भीगने से अपने को बचाने के लिए मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ता है तो पत्थर-बाजी कर-करके उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, यह बात भी सदन में आई । इसी तरह से फतेहपुर में पिछले दिनों जो आदिवासी लोगों के बाईस-बाईस घरों को जलाया गया, उजाड़ा गया । देश में सारी जगहों पर ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, इस समय मैं उन घटनाओं में नहीं जाना चाहता, लेकिन यह जो सारी घटनाएं हो रही हैं, यह हमको चौंकाने वाली हैं, देश को चौंकाने वाली हैं । तथा बहुत चिंता का विषय है और इसीलिए शर्म से हमारा माथा झुकता है कि आखिर क्या हो रहा है । जब ऐसी स्थिति आ रही है तो इसमें हमें जरूर कुछ कारणों की तरफ ध्यान देना होगा कि आखिर वे कौन से कारण हैं ? इसमें सामाजिक कारण भी हैं, आर्थिक कारण भी हैं । इसीलिए संविधान निर्माताओं ने जिस समय संविधान बनाया जा रहा था, उस समय जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन सभी शब्दों को जोड़कर के जो संकल्प लिया था इस देश को बनाने का, उसके आधार पर संविधान में बहुत सी व्यवस्थाएं हुई, उनके आधार पर बहुत से कानून भी बने, लेकिन उसके बावजूद भी इतने दिनों बाद तक भी हमें इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चिंतन करने का, मनन करने का और बहस करने का समय आ रहा है, जो अपने आप में एक गंभीर बात है । इस आधार पर मैं माननीय मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि बहुत सी चीजें हैं, जैसे

एक तो समाज के लोगों को भी सोचना पड़ेगा जो हमारे यहां जाति-प्रथा रही है, जिस जाति-प्रथा के रहते हमारा देश कभी गुलाम भी हुआ था और आजादी के बाद भी जिस तरह से जाति-प्रथा चली आ रही है, यह एक सामाजिक अभिशाप है और उससे जो छूत-छात और ऊंच-नीच का भेदभाव है, यह हमारे देश के लिए आज भी कलंक की बात है । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस चीज को समाप्त करने के लिए उसे राष्ट्रीय आन्दोलन से जोड़ने का काम किया था, आजादी के बाद जिस तरह से संविधान निर्माताओं ने संविधान में व्यवस्था दी थी, उसके बावजूद भी जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये कानून में आने वाली नहीं हैं। इनसे तमाम स्तरों पर निपटना होगा, सामाजिक स्तर पर निपटना होगा । सारे देश के, समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर ह क्या कर रहे हैं? अंतर्मुखी सोचकर के सोचना पड़ेगा और सोकप के उस दिशा में प्रयास करना होगा कि जो अस्पृश्यता एवं ऊंच नीच का भेदभाव समाज के लिए और देश के लिए एक राष्ट्रीय कलंक बना हुआ है, उसे धोने का काम करने के लिए हम किस तरह से प्रयास करें, इस पर विचार करना पड़ेगा और इसे करने के लिए अंतरजातीय विवाह की तरफ भी ध्यान देना होगा । मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि कोई ऐसा कानून भी बने, इस पर विचार किया जाए । जो लोग इस तरह से अंतरजातीय विवाह करते हैं, उनको सरकारी नौकरियों में या दूसरी सुविधाएं देने के लिए क्या सरकार विचार करेगी?

साथ ही साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या देश के अंदर रही है, लेकिन अब जैसे-जैसे शिक्षा बढ़ती चली जा रही है तो जो सम्मान से जीने की भावना है, जो हजारों बरसों से पीड़ित समाज के मन में—अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी और महिलाएं भी उपेक्षित रही हैं, उनके मन में जो सम्मान से जीने की भावना आ रही है, यह भी एक कारण है और उस कारण की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए ।

बहुत से झगड़े, जो दिखाई पड़ते हैं, वे जमीन के झगड़े होते हैं । आज आजादी के इतने दिनों बाद भी जमीन जोतता तो है किन्तु गरीब है, खेत पर काम करता है, मेहनत करता है, लेकिन जमीन उसके नाम नहीं हो पाती, दूसरों के नाम ही जमीन रहती है । जमींदारी प्रथा का अंत हुआ, बहुत सी जमीनें मिलीं लेकिन आज तक किन्हीं कारणों से जिस तरह से वह जमीन गरीब समुदाय को मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है, इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए । इसके साथ ही साथ इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि जो हजारों मुकदमें लैंड सीलिंग के अदालतों में चल रहे हैं, उनके निपटारे की व्यवस्था होनी चाहिए और उस जमीन का बंटवारा उस समाज के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के बीच में होना चाहिए ।

एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे जंगल हैं, उन जंगलों में आज हमारे सारे प्रोजेक्ट्स दिखाई देते हैं । आदिवासी उससे प्रभावित होते हैं, उनके लिए भी समय-समय पर जो पुनर्व्यवस्था का प्रश्न होना चाहिए, वह भी नहीं हो पाता है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो रिजर्वेशन का कोटा है, यह कोटा पूरा नहीं हो पा रहा है और मैं यह बहुत अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय एक लाख ग्यारह हजार से ऊपर सरकारी नौकरियों में बैक-लॉग पड़ा हुआ है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का । राजीव गांधी थे, हमारे नेता थे, देश के नेता थे, प्रधान मंत्री थे, उन्होंने इस बात को ध्यान में रखकर के, यह जो कोटा पड़ा है बैक-लॉग का, विचार किया कि किस तरह से हम आरक्षण के कोटे को पूरा करें और उन्होंने विशेष अभियान चलाने का काम किया था । मैं चाहूंगा कि फिर इस दिशा में कदम उठाकर के विशेष अभियान चलाने का काम किया जाए ताकि जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग

[श्री राम नरेश यादव]

हैं और जिनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हो रहा है, उनका कोटा पूरा हो सके । महोदय, मैं उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री था, हमने देखा कि जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हैं, हमारे यहां आरक्षण था 18 फीसदी अनुसूचित जाति, 2 फीसदी अनुसूचित जनजाति हमने देखा कि वह पूरा नहीं हो रहा है, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी में पूरा नहीं हो रहा है तो हमने 25 फीसदी और 30 फीसदी—तृतीय श्रेणी में 25 फीसदी और चतुर्थ श्रेणी में 30 फीसदी आरक्षण को बढ़ाने का काम किया था ताकि वह भी कोटा उस आधार पर पूरा हो सके । साथ ही

5.00 P.M.

साथ हमारे लिये अभिशाप की एक बहुत बड़ी चीज है और वह है कि हमारे समाज के कुछ लोग अपने सिर पर मैला ढोने का काम करते हैं, घरों से निकालते हैं, हमारी महिलायें करती हैं, समाज के लोग करते हैं । हमने घोषणा-पत्र में इस प्रथा को समाप्त करने के लिए पांच साल के लिये कहा है । लेकिन माननीय मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि नयी सरकार है और आप समाज कल्याण मंत्री हैं, ऐसी व्यवस्था करें कि तीन साल के अंदर ही यह समाज के लिये जो अभिशाप बना हुआ है उसको खत्म करने का काम करें । यह भी समाज के लिये बहुत बड़ी देन होगी । साथ ही साथ समाज के इन लोगों की शिक्षा भी नहीं हो पा रही है । बहुत से स्कूलों में सबसे अधिक जो ड्रौप आऊट है यह हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग और घरों की हमारी बच्चियां हैं, आखिर जब तक शिक्षित नहीं होंगी तो राष्ट्रीय धारा से कैसे जुड़ेंगी ? इसलिये आपको इस तरह की व्यवस्था करनी होगी ताकि समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर वह शिक्षित हो सकें और शिक्षित होने के बाद राष्ट्रीय धारा से जुड़ सकें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि इस पर गंभीरता के साथ सरकार ध्यान दें ताकि यह समस्या राष्ट्रीय स्तर पर हल हो सके । धन्यवाद ।

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद । महोदय, वैसे तो दलितों पर होने वाले अत्याचारों की बड़ी लम्बी दास्तानें हैं और बड़ी दिल दलहलाने वाली दास्तानें है, चाहे वह बिहार के बेलची, पिपरा या पारसबीघा या मधेपुरा कांड हो, चाहे उत्तर प्रदेश का पनवाडी, रूदायन फतहपुर या साढ़ू और देवली कांड हो जिसमें दो-दो दर्जन लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया, या फिर मध्य प्रदेश का सलैया कांड हो, जिसमें दलित महिलाओं को सिर्फ इस खुशी में और इसलिये नंगा नचाने की कोशिश की गयी कि वहां कांग्रेस की सरकार नहीं, बल्कि भाजपा की सरकार आयी । और चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश की तो अभी नयी-नयी घटनायें हैं, जिन पर यहां चर्चाएं हो रही हैं । अभी हमारी बहिन सुषमा जी कह रही थी कि मराठवाड़ा में दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है । तो मैं यह कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो मंदिर की राजनीति की थी । इसमें दलितों की भावनाओं के साथ भी खूब खिलवाड़ किया गया, मैं तो खुश होती..... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : हमने उस मंदिर का शिलान्यास हरिजन से करवाया । देखा गया है कि यहां जितने भी भाषण हुये हैं वह दलगत निष्ठाओं से ऊपर उठकर हुये हैं । आप पहली बार इसका राजनीतिकरण कर रही हैं । लेकिन अगर भाजपा की बात सुनना चाहती हैं तो... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Please, don't interrupt.

श्रीमती सुषमा स्वराज : तो मैं रिकार्ड पर लाना चाहती हूं कि मंदिर का जो शिलान्यास हुआ था वह भाजपा ने हरिजन से करवाया था ।

श्रीमती सत्या बहिन : मैं दलगत राजनीति की बात नहीं करना चाहती हूं... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप शुरु से भाजपा-भाजपा बोल रही हैं कि भाजपा मंदिर की राजनीति करती है, तो भाजपा ने मंदिर का शिलान्यास एक हरिजन से कराया ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Please, Sushma Swaraj, Don't interrupt.

श्रीमती सत्या बहिन : मैं तो यह निवेदन करना चाहती हूं कि... (**व्यवधान**) वोटों की राजनीति की... (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Don't enter into arguments; otherwise, I shall call the next speaker. Please be brief and make your points. (*Interruption*) Ms. Sushma Swaraj, don't enter into arguments. This is not the time to enter into arguments.

श्रीमती सत्या बहिन : उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं नाम नहीं लेती, लेकिन निवेदन इतना जरुर करना चाहती हूं कि मंदिर की राजनीति करने वाले, यह अगर मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश से ही आंदोलन शुरु करते तो उनको सही व सच्चा जन समर्थन मिलता । परन्तु वह मंदिर की राजनीति केवल वोटों की खातिर करते हैं.... (**व्यवधान**)

दूसरी बात, महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि अधिकतर दलितों की केवल भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है, केवल कोरी, मुंह जबानी सद्भावना और भावना की राजनीति की जाती है । कर्तव्यपूर्ण भावना ताक पर रख दी जाती है । महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि जितने राजनीतिक दल हैं, अगर वह सिर्फ अपने कर्तव्य का ही पालन करें कि हमें दलित समाज के लिए क्या करना है ? चाहे वह राजनीतिक दल हों, चाहे वह आजादी के बाद का समाज हो, चाहे वह सरकार रही हो, चाहे कोई भी सरकार रही हो, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लेना चाहती हूं । मंडल के नाम पर भी दलितों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ही किया गया । मैं कहना चाहती हूं कि हमारे नेता श्री राजीव गांधी जब प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने मेरे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 14 अप्रैल को बाबा साहेब डा० आम्बेडकर की जन्म शताब्दी पर डा० आम्बेडकर के नाम पर एक विश्व विद्यालय की आधारशिला रखी । लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार दुर्भाग्यवश नहीं रही और उसके बाद आने वाली सरकारों ने मंडल की राजनीति की और जिन्होंने केवल वोट की खातिर जातीय भावनाओं को उभारा, उन लोगों ने उस पर आगे कोई काम नहीं किया । पिछली सरकार ने भी और इसके बाद दो सरकारें आई, प्रदेशों में भी और केंद्र में भी..... (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Please don't interrupt.

श्रीमती सत्या बहिन: लेकिन जो सच्चाई है वह तो मैं कहूंगी ही । मैं यह कहना चाहती हूं कि दलितों की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ न हो, इसके लिए ठोस उपाय किए जाएं, कानून बनाए जाएं तभी इस पर सही मायनों में काम हो सकता है । हम केवल सदन में चर्चा करके या फिर किसी मंच पर भाषण करके दलितों का उद्धार नहीं कर सकते । इस संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं । जहां-जहां पर दलितों पर अत्याचार होते हैं, वहां पर उन अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए । महोदय, जहां भी दलितों के ऊपर अत्याचार होते है, वहां उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है । मैं सुझाव देना चाहती हूं कि जब भी खबर मिले तब रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए । इसके लिए कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए और वहां के अधिकारियों पर इसकी जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए और सांसदों पर विधायकों पर भी इसकी जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए ।

मेरा एक निवेदन यह है कि जहां पर अत्याचार होते हैं वहां पर उन सवर्ण लोगों के लाइसेंस जब्त किए जाने चाहिएं । जहां पर अत्याचार होते हैं, अगर वहां वे लाइसेंसधारी लोग दलितों की सुरक्षा के लिए आगे नहीं आते बल्कि

श्रीमति सत्या बहिन]

अत्याचारियों के साथ खड़े हो जाते हैं अतः इस बात की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए कि उन लोगों के लाइसेंस जब्त किए जाएं । महोदय, दलितों की आत्मरक्षा के लिए भी शस्त्र लाइसेंस की व्यवस्था की जानी चाहिए । इसके बारे में मैंने कल भी विशेष उल्लेख के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया था कि इसके लिए कुछ अनिवार्य प्रशासनिक व्यवस्था की जानी चाहिए ।

एक बात मैं यह कहना चाहती हूं कि दलितों पर जहां भी अत्याचार होते हैं वहां मुआवजे की राशि कुल 10,000 रुपए दी जाती है । मैं पिछले दिनों मध्य प्रदेश में गई थी जहां सलैया में एक कांड हुआ था । तो वहां के गृह मंत्री ने कहा था कि 10,000 रुपये से ज्यादा हम नहीं दे सकते । महोदय, जब भी कोई रेल दुर्घटना होती है तो मरने वाले रेल यात्री को एक लाख रुपया दिया जाता है ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Please conclude.

श्रीमती सत्या बहिन : मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहती हूं कि जहां पर दलितों पर, महिलाओं पर और वीकर सैक्शंस पर अत्याचार हों तो दंड एवं मुआवजे की राशि दोनों को बढ़ाया जाना चाहिए और इसको 2 लाख रुपए करना चाहिए । मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जहां शिक्षा का प्रसार नहीं होता है, जो क्षेत्र पिछड़े होते हैं वहां पर दलितों पर अत्याचार ज्यादा होते हैं । तो शिक्षा के प्रसार पर भी ध्यान देना चाहिए ।

महोदय, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात हमारे साथी राम नरेश जी ने कही है कि हमारे यहां अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए । जो लोग अंतरजातीय विवाह करें उनको प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाना चाहिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): There is no need for explanation. Please conclude.

श्रीमती सत्या बहिन : महोदय, आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में भी कुछ काम किया जाना चाहिए । इन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाए । महोदय, दलितों के लिए स्वरोजगार योजना का भी प्रावधान होना चाहिए और उनको बैंकों से उदारतापूर्वक धन दिया जाए ताकि वे अपना रोजगार चला सकें और अपनी दयनीय दशा से उबर सकें । धन्यवाद ।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, it is a fundamental and a very important issue and it is not going to be settled in the immediate future. The issue has prevailed in the Sub-Continent for the last 2000 years. The hon. Minister has read a statement. The information given in the statement is not very comprehensive. For example, from the statement we cannot find out whether the atrocities have increased or decreased. We all of us know that the atrocities have increased throughout the country. We do not want to accuse any political party or any particular Government in any State. This is a common issue which is affecting the whole country. Therefore, we have to see it in the national perspective cutting across party lines. Has the Government tried to find out the cause of this malady? What I feel is that after independence, scientific knowledge has developed in India but there is no scientific approach.

The so-called Harijans are supposed to be men of God, but God himself has not saved them for the last two thousand years. They are facing acute humiliation and they undergo torture, rape, naked terror, burning, etc. and many other types of atrocities are committed against them. But one thing we can find out. The root cause for this is that we are practising the Varnashrama Dharma. Until and unless the Varnashrama Dharma is completely banished from the minds of the people, these evils cannot be eradicated at all. We have passed so many laws and the

Constitution also has many provisions. If, in spite of these laws, these atrocities are still committed, it is because of the Varnashrama Dharma. The Manu Smriti should be banned in this country and wherever we find, we must burn this book or bury it five fathom deep.

Coming to the statement made by the Minister, I would like to point out one thing. Two or three things have been mentioned in particular in the statement and yet it is very vague. Firstly, it says that there will be a National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Secondly, it says that it has been decided to set up a Control Room in the Department of Welfare shortly. Thirdly, it says that the Prime Minister has also expressed his eagerness to call a meeting of all the Chief Ministers. The first point in the statement is vague because it says that "There shall be a National Commission". It is yet to be set up. The second point in the statement says, "It has been decided to set up a Control Room....". It has only been decided. That is all. The third point is that the Prime Minister "has expressed his eagerness to call a meeting .....". It means that the Prime Minister has not at all decided to call a meeting of the Chief Ministers, but he has only expressed his eagerness. Therefore, on these counts, I feel, the statement is unsatisfactory. In this manner, I think, we cannot settle this issue and solve this problem.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): O.K. Now, you conclude.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Therefore, what I want to say is that the Government should take some concrete action. Otherwise, we cannot settle this issue in this manner. For that purpose, we must develop the scientific approach among the people in this country rather than scientific knowledge alone. Thank you, Sir.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, may I make a submission? Since the Home Minister is here now and since this problem concerns his Ministry also, may I request the Home Minister to make an intervention and say something on the growing atrocities on the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes?

श्रीमती रेणुका चौधरी : मंत्री जी, महिलाओं की क्या परिस्थिति है, वह भी सुना दीजिए ।

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, अपने आदरणीय सदस्यों के सुझाव और विचार मैं बहुत गौर से सुन रहा था । यह साफ है कि सदियों का यह कोढ़ है एक-दो वर्षों का या 40-50 वर्षों का नहीं है, यह 3 हजार वर्षों का कोढ़ है । बी० सी० 500 में ये चांडाल के रूप में कहे जाते थे । फिर ए. डी. 1700, 1800 और 1900 में यह अनटचे बल या अछूत हुए । उसके बाद 20वीं सदी में यह हरिजन कहे जाने लगे और आज इनको अनुसूचित जाति की संज्ञा दी गई है ।

एक माननीय सदस्य : 21वीं सदी में क्या कहे जाएंगे ?

श्री सीताराम केसरी : 21वीं सदी में आगे आने वाले दिन बताएंगे । लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता हैं कि आज सभ्य संसार में जो सभ्य राष्ट्र हम कहे जाते है जिसके हम सभी देश सदस्य हैं, एक भी हरिजन का खून या एक भी बहन के आंसू हमारे लिए दाग है, हमारी सभ्यता के चेहरे पर काला धब्बा है । जिस समय मेरी बहन बोल रही थी उसकी पीड़ा मेरे हृदय में टीस पैदा कर रही थी । मैं भी सोच रहा था कि वह सत्य ही बोल रही हैं, कहीं उसमें अधिकता नहीं है, कहीं उसमें अतिशयोक्ति नहीं है । यह भी सत्य है कि मैंने जो वक्तव्य आपके सामने रखा वह सरकारी विवरण है और जो आपने मांगा उसके आधार पर यह विवरण देना ही था । मगर आपने अपने वार्तालाप के मध्य सामाजिक कुरीतियों की ओर मेरा व अपना ध्यान दिलाया ।

गुरूदास दास गुप्त जी ने एक बड़ी इम्पोर्टेन्ट बात उठाई है आर्थिक व्यवस्था के बारे में । यह सत्य है कि जमीन की चकबंदी के अभाव में जमीन को लेकर बात हो रही है । इतना ही नहीं इसके अलावा

[श्री सीताराम केसरी]

उनके सम्मान पर उतना नहीं, बल्कि, जो सामाजिक निहित स्वार्थ अपर जाति के लोग हैं उनका उन पर दबाव है । जिस समय एक खाट पर बैठ कर एक अछूत या गरीब को जाते हुए देखता है और जब वह अछूत या गरीब बेचारा उठता है तो खाट पर बैठने वालों के कलेजे में चोट होती है । वह चोट का परिणाम है हिंसा । हर गांव का यह दस्तूर है । आप सत्य कह रहे हैं । हम आपकी भावनाओं के साथ है । मालवीय जी आपने जो बातें कहीं, मैं आपको बताऊं कि आज से आप 80 वर्ष पूर्व चले जाइये, गांधी जी के युग को याद कीजिए । 1918 में त्रिवेन्द्रम में क्या हुआ । त्रिवेन्द्रम के मंदिर में 500 फीट की दूरी तक कोई हरिजन नहीं जा सकता था । कोई अछूत प्रवेश नहीं कर सकता था । यही वजह है कि तमिलनाडु में परियार का जन्म हुआ । सामाजिक कुरीतियों ने, सामाजिक अत्याचार ने, सामाजिक रूढ़िवादियों की विशेषकर हिन्दू धर्मावलम्बियों की, मठाधीशों की, महापंडितों की, पांडवों की, पुजारियों की वजह से वर्षों से समाज कई भागों में विभाजित होता गया । कुछ लोग क्रिश्चन हो गये, कुछ लोग बुद्धिस्ट हो गये, कुछ लोग इस्लाम में चले गये । आज भी अत्याचार का अभाव नहीं है, यह सत्य है । आपने ठीक निर्देश दिया मालवीय जी कि मराठवाड़ा में क्या हो रहा है । एक मराठवाड़ा हो तो हो, किस गांव में मराठवाड़ा नहीं है । पुलिस हो या सीताराम केसरी मंत्री हो या आप सदस्य हों, चाहे विरोधी दल हो या यह दल हो, वह दल हो सामाजिक कुरीतियों की हम सभी जर्जर अवस्था में बैठे हुए हैं । इससे मुक्त होना होगा ।

श्री आर० के० धवन (आन्ध्र प्रदेश) : कैसे मुक्त होंगे यह बताइये ।

श्री सीताराम केसरी : गांधी जी ने संदेश दिया था कि सामाजिक अन्याय का अंत करो । जब स्वराज की लड़ाई लड़नी थी तो उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था ? सामाजि विषमता का अंत किया था । अछूतों का नाम हरिजन इसलिए नहीं रखा कि जिनको अछूत समझा जाता था उनको कहा गया की हरिजन ये हैं तुम नहीं हो । इसका मतलब यह था कि उनकी भर्त्सना थी, समाज के उस अंग की भर्त्सना थी जिसने उनको वर्षों से अछूत बना कर रखा था । मालवीय जी आपने ठीक कहा । एक बात का मैं आपको उत्तर देना चाहता हूं कि जो आपने आयोग की बात कही उस आयोग को स्टेट्युटरी पावर दी जा रही है और उसका फैसला हो चुका है । उस आयोग के अन्तर्गत हरिजन, आदिवासी का आयोग बनेगा । उसके अन्तर्गत किसी को भी बुलाकर गवाही ले सकते हैं । घटनाक्रम की छानबीन कर सकते हैं । गुरूदास दास गुप्त जी ने लेंड रिफार्म के बारे में कहा था । हमारे प्रधान मंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की थी की लेंड रिफार्म हम शीघ्र लायेंगे और इस दिशा में वह सक्रिय कदम उठायेंगे । श्री राम नरेश जी ने दो शब्द उठाये हैं । उनके बारे में मैं कह देना चाहता हूं । उन्होंने रिजर्वेशन के बैकलॉग के बारे में कहा । इस दिशा में भी मैं सीरियसली सोच रहा हूं । हरिजनों का जो बैकलाग होता है, रिजर्वेशन का कोटा होता है, चाहे क्लास 'ए' का हो, चाहे क्लास 'बी' का हो, मैं अब इसको लेजिस्लेटिव रूप की बात सोच रहा हूं । मैंने इस दिशा में अपने विभाग को कदम बढ़ाने के लिए कहा है । मैं चाहता हूं कि बैकलॉग का डिरिजर्व न किया जाय, जनरल पूल में न लिया जाये, उसको कैरी फारवर्ड कर दिया जाये, इस विचार को मैं मानने वाला हूं ।

जहां तक नाइट साइल की बात है, वास्तव में यह सभ्यता पर दाग है । अब तक अब तक इस सरकार का और इसके पूर्व की सरकार का कोई पच्चीस करोड़ का प्रावधान था । मैंने वित्त मंत्री से लड़कर इसको 50 करोड़ करा दिया है । 250 करोड़ मैंने पंचवर्षीय योजना में आवंटित करा लिये हैं । अब तक 25 करोड़ का प्रावधान था और अब मैंने इसको 50 करोड़ का प्रावधान करा लिया है । सिवाय 25 सौ करोड़ से कम में काम चलने वाला नहीं है । 25 करोड़ से 50 करोड़ इस आर्थिक संकट के समय में उन्होंने मान लिया है । हम बनिया हैं, धीरे धीरे बढ़ाकर

इसको हम लेंगे, इतना मैं विश्वास दिला देना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि 5–6 वर्षों में इसको एबालिश कर दिया जाएगा, यह मैंने योजना बनाई है।

श्री रामनरेश यादव : तीन-चार साल में यह राष्ट्रीय काम हो जाएगा, इससे बड़ा काम कोई दूसरा हो नहीं सकता है।

श्री सीताराम केसरी : डा० अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कोई अनुदान नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूं कि 2 करोड़ 4 लाख रुपयों का अनुदान हमने दिया है, यह मैं आपको विदित करा देना चाहता हूं। मालवीय जी ने बहिनों के संबंध में कहा और दूसरे वीकर सेक्सन के बारे में कहा। उन्होंने आरोप लगाने के साथ-साथ मुझे आरोप मुक्त भी कर दिया कि यह गृह विभाग से संबंधित है। मगर फिर भी हम लोग कलेक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी के अन्तर्गत इसको लेते हैं और इसकी तालिका आगे हम देंगे, इस बात से हम आपको आश्वस्त कर देते हैं। किसी ने यह बात उठाई कि समाज में वीकर सेक्शन पर होने वाले अत्याचारों की जिम्मेवारी सरकार पर है। सरकार की जिम्मेवारी को मानते हुए हम अपना व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी समझते हैं इंसानियत के नाते। मेरे बन्धुओं मैं समझता हूं कि सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिये हैं।

[उपसभापति महोदया पीठासीन हुईं]

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, at the beginning I had raised the question that the Minister did not give to us any statistics so far as the incidents relating to atrocities among the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weakre sections are concerned. I would like the Government to tell the House in how many cases the delinquent officers, responsible for dereliction of duty, were punished, because I had given him statistics that in one single year there have been more than 1200 cases of outrage. Therefore, just to prove the *bona fides* that the Government is bent upon taking some strict measures, will the Government tell us, in how many cases the officers, the policemen and custodians of law and order have been punished? Thirdly, Madam, I had requested the Minister, on the question of law, for the agricultural workers and other rural workers what is the attitude of the Government, because the National Commission had submitted the report that to improve the economic condition they need protection?

The third question I put is: What is the attitude towards the report of the Rural Commission on workers?

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: I want a humble suggestion to be taken if the Minister considers it right. Crime against women irrespective of what community you belong to or what party you belong to is a national crime. This cannot be equated to monetary compensation. You cannot equate. औरत के साथ बलात्कार हो गया उसको 30 रुपये, सौ रुपये दे दिये या नौकरी दे दी। Crime against women is not punishable by payment of monetary claim. It has to be a physical punishment. They have to be imprisoned.

उसकी तस्वीर उतार दो और अखबार में छाप दो और हर पुलिस स्टेशन पर उसकी तस्वीर रहे। This man is offender against women.

श्रीमती सत्या बहिन : उपसभापति महोदया, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहती हूं कि मंत्री महोदय के बयान में है प्रधानमंत्री समस्त मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलायेंगे, हरिजन और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों पर विचार करने के लिये। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, क्या उस संबंध में भी आप अलग से मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलायेंगी और उसमें किसी नीति का निर्धारण करेंगे? और दूसरा यह कि इस बारे में जो रोज खबरें आ रही हैं उनको देखते हुए क्या आप इस दिशा में ठोस कदम उठायेंगे?

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: As far as atrocities on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned, will the Government....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Did you speak on this subject?

श्री सीताराम केसरी : : मान्यवर ।

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: I am just asking a specific question.

उपसभापति : आप तो बोल चुके हैं । आपको पहले ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहिये था ।

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: What does the Government intend to do as far as atrocities are concerned? Is the Government bringing a White Paper on it?

श्री सीताराम केसरी : आदरणीय उपसभापति महोदया, जहां तक गुरुदास दास गुप्ता जी का प्रश्न है कि क्या कुछ आफिसरों को किसी तरह का पनिशमेंट दिया जायेगा जिन्होंने सर्विस में, सेवा में इसको इग्नोर किया है । तो मैं इसके बारे बारे में पूरी छान-बीन करके सारी तालिका पेश कर दूंगा ।

जो बहिन ने कहा कि जो मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है, उस सम्मेलन में क्या बहिनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उस पर विचार होगा, तो निश्चित ही विचार होगा । इस बात का आप ध्यान रखें कि कोई भी अट्रोसिटी अगर वीकर सेक्शन पर होती है तो चाहे हरिजन हों, आदिवासी हों, बहिनें हों, बेटियां हों, बच्चे हों, ये कमजोर वर्ग के हैं और इन सब का मतलब वीकर सेक्शन होता है । इसलिये बहिन विश्वास रखें कि इस मुख्य मंत्री सम्मेलन में इन सारी चीजों पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Calling Attention is over. We will take up the Code of Criminal Procedure (Second Amendment) Bill, 1991. (*Interruptions*).

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: This particular Bill was defeated in this House and within a span of less than a month it is being brought back through the back-door and the Government is arguing that the Bill has been changed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let us move the motion first.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: We strongly protest against the backdoor introduction of a Bill that has fallen through in the House.

SHRI MENTAY PADMANABHAM: Madam, may I make a submission? This Bill was defeated in the last Session not because we wanted to embarrass the Government; we really felt that this Bill is uncalled for. We felt that this Bill is a slur on the federal system of this country. So, we defeated this Bill. But the Government is saying that they have made some changes. If you go through the Bill, you will find that the changes are cosmetic.... (*Interruptions*). Really, no change has been effected in the Bill. The spirit of the Bill still remains the same. Changes made by the Government are simply a way to bring it back in this session. So, we strongly object Government's taking up this Bill at this stage.

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : उपसभापति महोदया, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि 5-8-1991 को जब यह बिल माननीय गृह मंत्री ने इस सदन में प्रस्तुत किया था तो सत्ताधारी दल के ही एक माननीय सदस्य श्री एस० एस० अहलुवालिया ने उसको निरस्त करने का प्रस्ताव रखा था। उपसभापति महोदया, इस सदन के इतिहास में शायद वह पहला मौका था जब सत्ताधारी दल के माननीय सदस्य का जो प्रस्ताव आया उसमें विपक्षी दलों ने सत्ताधारी पक्ष के सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन किया और उसके कारण सरकार की हार हुई । सदन के इतिहास में, जनतंत्र के इतिहास में एक बहुत बढ़िया अध्याय की शुरूआत हुई । यदि कोई अच्छी बात उधर से आती है तो हम सपोर्ट करते हैं । यह दूसरी बात है कि हमारी कोई भी अच्छी बात को सत्ताधारी दल के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं । मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, मैंने उस दिन भी कहा

था जब गृह मंत्री महोदय ने कल सदन के सामने यह बिल प्रस्तुत किया तो मैंने कहा था कि आपने जो कारण इसके अन्दर दिये हैं कि आपको क्यों इस बिल को पुन: लाना पड़ा, आपको इस में यह कहना चाहिये था कि हमारे ही सत्ताधारी पक्ष के एक सदस्य के कारण हमारी हार हुई जिसके कारण पुन: हम को यह बिल लाना पड़ा। निश्चित रूप से मैंसमझता हूं कि फिर जबकि लगभग वही कार्य चल रहा है, सदन और लोकतंत्र के लिए यह कभी भी मर्यादापूर्ण नहीं होगा कि गृह मंत्री जो इस बिल को इस तरह से लाएं। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री महोदय भी इसको पेश नहीं करेंगे।

SHRI SUKOMAL SEN: It is highly objectionable, improper and unethical that the Government has come again with the Bill which was defeated in the House, not to put the Government to any difficulty but only in principle. At that time we fought on principle that this Bill affects the Centre-State relations and it is an attack on the States' rights. So we opposed the Bill and it was defeated. Again the Government is coming up with the Bill with the same substance. So it is improper and unethical and we strongly object to it.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उपसभापति महोदया, आपको स्मरण होगा जब दो दिन पहले इंट्रोड्यूस किया गया था तब मैंने अपने दल की ओर से विरोध किया था कि यह इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिये। मैं इसका विरोध करता हूं। यह टेक्नीकली वही बिल ला रहे हैं लेकिन इस सदन में यह डिफीट किया गया बिल है जिसकी धाराएं भी अनुचित हैं। जैसे मेरे सहयोगियों ने कहा, हमने केवल विरोध करने के लिए ही इसका विरोध नहीं किया था। सौभाग्य है हम लोगों का कि हमारे साथी ने उधर से प्रस्ताव रखा, हमने उसको स्वीकार किया। यह एक प्रकार से सदन की अवमानना है टेक्नीकल कुछ भी हो। इसलिए हम लोग कम से कम मेरा दल और बहुत से विरोधी दल अपने को इसके संबद्ध नहीं कर सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्शन है, यदि सब सहयोग करेंगे तो हम जो भी पग उठायेंगे वह आपके सामने आ जाएगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : उपसभापति महोदया।

श्री शंकर दयाल सिंह : मालवीय जी आप लोग तो यह बिल लाए थे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : उपसभापति महोदया, इस संशोधन का असर पंजाब में भी पड़ेगा जहां राष्ट्रपति शासन है। इसकी चर्चा इस में है। इसमें नोटिफिकेशन हुआ है 30 जून को कि 25 सितम्बर तक पंजाब में चुनाव करा लिये जाएंगे और 30 सितम्बर तक पंजाब विधान सभा गठित हो जाएगी लेकिन चूंकि चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, इसके विरोध में मे सदन से बहिर्गमन करता हूं (व्यवधान)

श्री शंकर दयाल सिंह : यह बिल्कुल अनैतिक है। (व्यवधान) Therefore, I walk out.

SHRI MENTAY PADMANABHAM: We appeal to the Government to withdraw the Bill. But if they are not withdrawing, in protest, we walk out.

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (SECOND AMENDMENT) BILL, 1991

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 be taken into consideration."

As the Hon'ble Members are aware, section 197 of the Code of Criminal Procedure, 1973 provides for the previous sanction of the Central Government or, as the case may be, the State Government before a court took cognizance of an offence alleged to have been committed by any public servant including